साप्ताहिक

आरएनआई न. :- जेकेएचआईएन/25/ए0631

सबका जम्मू कश्मीर

हिन्दी • वर्ष: 2 • अंक: 8 • कठुआ, शनिवार 21 फ़रवरी 2026 • पृष्ठ: 16 • मूल्य: 5 रूपए

आईटी मंत्री वैष्णव के मुताबिक, 86 देशों और दो अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने एआई इम्पैक्ट समिट घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट घोषणापत्र पर 86 देशों और दो अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, डेनमार्क और जर्मनी शामिल हैं।

नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के समापन के अवसर पर इस घोषणा को वैश्विक स्तर पर मजबूत समर्थन मिला है।

वैष्णव ने पत्रकारों से कहा कि दुनिया भर के देशों ने श्सभी के कल्याण और सभी की खुशीश के सिद्धांतों को औपचारिक रूप दिया है और उनका पालन किया है।

मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानव–केंद्रित एआई दृष्टिकोण को विश्व ने स्वीकार कर लिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता संसाधनों का लो.

कतंत्रीकरण करके एआई सुविधाएं, सेवाएं और प्रौद्योगिकी समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना सर्वमान्य हो गया है।"

उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक विकास और सामा. जिक हित के बीच संतुलन बनाए रखने को प्राथमिकता दी गई है।

"केवल आर्थिक विकास ही नहीं, सामाजिक सद्भाव का भी ध्यान रखना होगा। सुरक्षा और विश्वास सर्वोपरि हैं, इन्हें मुख्य बिंदुओं में शामिल किया गया है," वैष्णव ने कहा, साथ ही यह भी बताया कि एक सुरक्षित, भरोसेमंद और मजबूत एआई ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

उन्होंने बताया कि अन्य प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार और मानव पूंजी का विकास शामिल है।

मंत्री ने कहा, "इन सभी क्षेत्रों में सभी देशों ने मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। अमे. रिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, डेनमार्क, मिस्र, इंडोनेशिया और जर्मनी सहित लगभग सभी देशों ने भाग लिया है।"

मेगा एआई इम्पैक्ट समिट ने अकेले बुनियादी ढांचे में 250 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता हासिल की, जिसे वैष्णव ने शुक्रवार को ष्शानदार सफलताष करार दिया।

वैष्णव ने कहा था कि शिखर सम्मेलन में पांच लाख से अधिक आगंतुकों ने भाग लिया, जो

■ शेष पेज 2...

भारत से नक्सलवाद का 31 मार्च तक खात्मा : गृह मंत्री अमित शाह

सबका जम्मू कश्मीर

गुवाहाटी : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित 31 मार्च की समय सीमा तक देश से नक्सलवाद का खात्मा कर लिया जाएगा।

पूर्वोत्तर में पहली बार आयोजित 87वीं सीआरपीएफ दिवस परेड को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि जम्मू–कश्मीर में, जहां पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य हो गई हैं, सीआरपीएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, मणिपुर में जातीय हिंसा से निपटने और केवल तीन वर्षों में माओवादियों की कमर तोड़ने में भी सीआरपीएफ और कोबरा बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि नक्सलवाद देश के 12 राज्यों और अनगिनत जिलों में फैला हुआ था, और जब केंद्र ने इस खतरे को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया, तो सीआरपीएफ और कोबरा बल के जवानों ने इस प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

गृह मंत्री ने कहा कि इतना बड़ा, जटिल और कठिन कार्य मात्र तीन वर्षों में पूरा किया गया।

उन्होंने जोर देकर कहा, सीआरपीएफ कर्मियों की बदौलत ही हम विश्वासपूर्वक कह घ्सकते हैं कि 31 मार्च, 2026 तक देश नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़–तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुटा पहाड़ियों

■ शेष पेज 2...

शांतमनु ने जम्मू-कश्मीर के सचिव के रूप में शपथ ली, स्थानीय निकाय चुनाव कराने के संकेत दिए

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : पूर्व नौकरशाह शांतमनु ने शनिवार को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में पांच साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में लंबे समय से लंबित पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के आयोजन के महत्व पर जोर दिया।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोक भवन में आयोजित एक समारोह में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को पद की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, जिनमें उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर

शामिल थे, उपस्थित थे। मुख्य सचिव अटल दुल्लू और पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात भी मौजूद थे।

समाचार एजेंसी से बात करते हुए शांतमनु ने कहा कि जिम्मेदारी संभालना उनके लिए ष्अत्यंत खुशी और गर्वष की बात है।

लंबित पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ष्ये चुनाव हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, विशेष रूप से विकेंद्रीकृत शासन और जमीनी स्तर के विकास को मजबूत करने में। चूंकि ये चुनाव कुछ समय से नहीं हुए हैं, इसलिए इनका होना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।ष "मुझे औपचारिक रूप से अपनी जिम्मेदारियां शुरू करते हुए खुशी हो रही है। मैं अपने कर्तव्यों

■ शेष पेज 2...

जम्मू–कश्मीर और उत्तराखंड में 750 किसानों को छह लाख लैवेंडर के पौधे मुफ्त में वितरित किए गए

सबका जम्मू कश्मीर

भदरवाह (जम्मू–कश्मीर) : लैवेंडर की खेती को और मजबूत करने के उद्देश्य से, जम्मू–कश्मीर और उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में 750 किसानों को लगभग छह लाख मुफ्त गुणवत्तापूर्ण पौध (क्यूपीएम) वितरित किए गए। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानक. ारी दी।

सीएसआईआर–आईआईएम जम्मू के लैवेंडर वैज्ञानिक संदीप सिंह चरक ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य इस सुगंधित फसल की खेती का विस्तार करना, किसानों की आय बढ़ाना और देश में लैवेंडर उत्पादन के केंद्र के रूप में इस क्षेत्र की बढ़ती प्रतिष्ठा को मजबूत करना है।

उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में भदरवाह की 50 नर्सरियों में मुफ्त पौध

■ शेष पेज 2...

जम्मू में वीजा धोखाधड़ी मामले में आरोपी व्यक्ति के आवास पर तलाशी ली गई

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू–कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच की स्पेशल क्राइम विंग ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के मामले में शनिवार को आरोपी के घर पर तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई पिछले वर्ष दर्ज एफआईआर के तहत की गई जांच के क्रम में की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि स्पेशल क्राइम विंग पुलिस स्टेशन, जम्मू में संबंधित धाराओं के

■ शेष पेज 2...

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

शेष पेज 1 से.....

आईटी मंत्री वैष्णव...

भारत के एआई प्रयासों के प्रति मजबूत घरेलू और वैश्विक जुड़ाव को दर्शाता है।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ने वैश्विक नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को एक साथ लाया, जिससे भारत को अंतरराष्ट्रीय एआई शासन और बुनियादी ढांचे के विकास को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया गया।

उन्होंने कहा था, "प्रदर्शनी में पांच लाख से अधिक आगंतुकों ने भाग लिया, बहुत कुछ सीखा और दुनिया भर के कई विशेषज्ञों से बातचीत की। विश्व के लगभग सभी प्रमुख एआई क्षेत्र के खिलाड़ियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कई स्टार्टअप्स को अपना काम प्रदर्शित करने का अवसर मिला। कुल मिलाकर, चर्चा की गुणवत्ता असाधारण थी।"

वैष्णव ने बताया था कि चाहे मंत्रिस्तरीय संवाद हो, नेताओं का पूर्ण सत्र हो, मुख्य उद्घाटन समारोह हो या समग्र रूप से शिखर सम्मेलन हो, भागीदारी और संवाद की गुणवत्ता अभूतपूर्व थी।

बुनियादी ढांचे से संबंधित पूंजी के लिए निवेश प्रतिज्ञाएं 250 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई हैं और वेंचर कैपिटल/डीप टेक निवेश पर लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर की निवेश प्रतिज्ञाएं हैं।

वैष्णव ने कहा था कि शिखर सम्मेलन ने नए एआई युग में भारत की भूमिका में दुनिया के विश्वास को प्रतिबिंबित किया।

इस सप्ताह दिल्ली में वैश्विक प्रौद्योगिकी जगत की कई दिग्गज हस्तियां मौजूद थीं दृ गूगल के सुंदर पिचाई, ओपनएआई के सैम अल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट के ब्रैड स्मिथ और एंथ्रोपिक के डारियो अमोदेई दृ जिन्होंने प्रौद्योगिकी जगत के सबसे चर्चित वैश्विक विषयों पर चर्चा की, जिनमें एआई के अवसर और जोखिम, एजीआई, शासन व्यवस्था और रोजगार का भविष्य शामिल हैं।

भारत से नक्सलवाद...

में अप्रैल–मई 2025 में चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में 31 नक्सलियों को मार गिराने के लिए सीआरपीएफ कर्मियों की प्रशंसा करते हुए शाह ने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों ने बेहद चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में 21 दिनों तक चले इस अभियान को अंजाम दिया, जिसमें भीषण धूप में 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सहन करते हुए नक्सलियों के गढ़ को ध्वस्त कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि असाधारण साहस का प्रदर्शन करते हुए, सीआरपीएफ के जवान उन 21 दिनों तक अत्यधिक तापमान से तपती पथरीली पहाड़ियों पर अभियान चलाते हुए एक इंच भी पीछे नहीं हटे और अंततः नक्सलियों के रणनीतिक अड्डे को नष्ट कर दिया।

शाह ने कहा कि सीआरपीएफ और कोबरा बल ने देश को ष्लाल आतंकष से मुक्त कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने बताया कि शनिवार को 14 सीआरपीएफ जवानों को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया, पांच को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पुलिस पदक मिला और बल की पांच बटालियनों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदकों से सम्मानित किया गया।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, सीआरपीएफ के महानिद. `शक जीपी सिंह और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

इससे पहले, सिंह ने कहा कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार द्वारा दी गई 31 मार्च की समय सीमा तक देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा।

शाह ने कहा कि सीआरपीएफ के 86 साल के इतिहास में यह पहली बार है कि बल का स्थापना दिवस समारोह पूर्वोत्तर, असम में आयोजित किया गया है, जो सभी के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। "2019 में यह निर्णय लिया गया था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की वार्षिक परेड देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित की जाएगी। और आज, सीआरपीएफ की परेड देश के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक – पूर्वोत्तर में आयोजित की जा रही है," उन्होंने कहा। देश

भर की विभिन्न इकाइयों से चुनी गई सीआरपीएफ की आठ टुकड़ियों ने यहां के सुव्यवस्थित सरुसजाई स्टेडियम में एक औपचारिक परेड प्रस्तुत की।

रंग–बिरंगी टोपी पहने और ढोल की थाप पर मार्च करते हुए, परेड ने विशाल जनसमूह से लगातार तालियां बटोरीं।

परेड का नेतृत्व 225वीं बटालियन के कमांडेंट दीपक धौंडियाल ने किया।

मार्च करने वाली इकाइयों में उत्तरी सेक्टर की टुकड़ियां शामिल थीं, जिनमें महिला कर्मी भी थीं, साथ ही उत्तर पश्चिमी सेक्टर, झारखंड, ओडिशा, रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ), कोबरा यूनिट और पश्चिमी और उत्तर पूर्वी सेक्टर की टुकड़ियां भी शामिल थीं।

समारोह का समापन सटीक प्रदर्शनों और सामरिक प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के साथ हुआ। महिला कर्मियों ने जटिल राइफल अभ्यास का प्रदर्शन किया, कमांडो ने उच्च जोखिम वाले बंधक बचाव अभियान का अभ्यास किया और कोबरा कमांडो ने नक्सल विरोधी अभियान का चित्रण करते हुए जंगल युद्ध अभ्यास किया।

शाह ने इस बात पर जोर दिया कि सीआरपीएफ के बिना भारत की आंतरिक सुरक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना से ही, यह बल कर्तव्यनिष्ठा के कारण आंतरिक सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ रहा है और परिणाम भी दे रहा है।

उन्होंने कहा कि 2,270 सीआरपीएफ जवानों ने भारत को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और पूरा देश उन्हें धन्यवाद देता है और श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

गृह मंत्री ने कहा कि कर्तव्यनिष्ठा और बलिदानों के कारण ही सीआरपीएफ जवानों ने कई मौकों पर देश की रक्षा की है। उन्होंने कहा,

"ग्यारह–बारह साल पहले, देश में तीन प्रमुख संवेदनशील क्षेत्र थे – जम्मू और कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र और पूर्वोत्तर – जो आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गए थे। आज, इन तीनों स्थानों पर शांति स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई है।"

शाह ने कहा कि एक समय इन तीनों संवेदनशील क्षेत्रों में बम विस्फोट, गोलीबारी, बंद, नाकाबंदी और तोड़फोड़ आम बात थी, लेकिन अब ये तीनों क्षेत्र विकास के इंजन बन गए हैं और पूरे देश के विकास को गति दे रहे हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सीआरपीएफ कर्मियों के बलिदान के बिना इन तीनों संवेदनशील क्षेत्रों को विकास के पथ पर लाना असंभव होता।

शाह ने बताया कि सीआरपीएफ की यात्रा 1939 में मात्र दो बटालियनों से शुरू हुई थी और आज 248 बटालियनों और 32 लाख कर्मियों की संख्या के साथ यह विश्व की सबसे बड़ी सीएपीएफ बन गई है। उन्होंने कहा कि कोलकाता में वामपंथी चरमपंथियों के हमले में 78 पुलिसकर्मियों की मौत के बावजूद, सीआरपीएफ ने साहस के साथ मोर्चा संभाले रखा। गृह मंत्री ने बताया कि बल ने संसद पर आतंकवादी हमले को नाकाम किया और 2005 में श्री राम जन्मभूमि पर हुए हमले को भी विफल कर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू–कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली और इसे सुनिश्चित करने में सीआरपीएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शाह ने आगे कहा कि सीआरपीएफ, बीएसएफ और विशेष रूप से जम्मू–कश्मीर पुलिस के महत्वपूर्ण योगदान के कारण जम्मू–कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य हो गई हैं, उद्योग स्थापित हो रहे हैं और विकास हो रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में शांति स्थापित करने में सीआरपीएफ ने बड़ी भूमिका निभाई है।

गृह मंत्री ने कहा कि चाहे अमरनाथ यात्रा हो या महाकुंभ, बल ने देश के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर में 700 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 780 और जम्मू–कश्मीर में 540। शाह ने

कहा, "इन बलिदानों के बिना आज इन तीनों संवेदनशील क्षेत्रों को विकास के पथ पर ले जाना असंभव होता। अगर मैं असम की बात करूं तो वहां 79 जवानों ने शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है।"

ब्रिटिश शासन के तहत 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस (सीआरपी) के रूप में बल की पहली बटालियन का गठन किया गया था। स्वतंत्रता के बाद, 1949 में, पहले गृह मंत्री वल्लभभाई पटेल द्वारा इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया।

शांतमनु ने...

का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करूंगा," उन्होंने कहा।

नगर परिषदों का कार्यकाल अक्टूबर–नवंबर 2023 में समाप्त हो गया, जबकि पंचायतों और ब्लॉक विकास परिषदों का पांच वर्षीय कार्यकाल 9 जनवरी 2024 को पूरा हो गया। जिला विकास परिषदों का कार्यकाल 24 फरवरी को समाप्त होने के साथ, जम्मू और कश्मीर में वस्तुतः कोई निर्वाचित स्थानीय निकाय कार्यरत नहीं रहेगा।

अधिकारियों ने बताया कि परिसीमन प्रक्रिया और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों के आरक्षण सहित कई कारणों से स्थानीय निकाय चुनाव समय पर नहीं कराए जा सके।

हाल ही में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि उनकी सरकार इन चुनावों को जल्द से जल्द कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है, लेकिन राज्य चुनाव आयुक्त का पद रिक्त होना एक बड़ी बाधा है।

जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम और संबंधित नगर पालिका अधिनियमों के तहत, राज्य चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और स्थानीय चुनाव कराने का अधिकार है।

17 फरवरी को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने शांतमनु को पांच साल की अवधि के लिए या उनके 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया।

शांतमनु, जो एजीएमयूटी कैडर के 1991 बैच के अधिकारी हैं और हाल ही में जम्मू और कश्मीर में अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, ने बीआर शर्मा का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2024 में समाप्त हो गया था।

जम्मू–कश्मीर और...

वितरित किए गए, जिसे व्यापक रूप से भारत की बैंगनी क्रांति का जन्मस्थान माना जाता है। चरक ने कहा

, ष्आईआईएम जम्मू ने डोडा और जम्मू–कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में उत्तराखंड के 400 किसानों और भदरवाह के 350 किसानों को छह लाख लैवेंडर के पौध प्राप्त कर वितरित किए हैं।ष उन्होंने आगे कहा कि यह प्रक्रिया जारी है और इस मौसम में और अधिक किसानों को पौध उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रगतिशील किसान और युवा उद्यमी तौकीर बागबान, जिन्होंने 2,500 किसानों को पारंपरिक मक्का की खेती छोड़कर सुगंधित लैवेंडर की खेती करने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित और प्रोत्साहित किया है, ने कहा कि पौधों का वितरण लैवेंडर किसानों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है।

श्भारत के लैवेंडर मैनश के नाम से मशहूर बागबान ने कहा, ष्सीएसआईआर–प्प्ड ने न केवल नर्सरी मालिकों से छह लाख पौधे खरीदे, बल्कि उन नए किसानों को मुफ्त पौधे भी वितरित किए जो पारंपरिक फसल से लैवेंडर की खेती की ओर रुख करना चाहते हैं।ष

उन्होंने इस सफलता का श्रेय केंद्रीय मंत्री जतिंदर सिंह के व्यक्तिगत प्रयासों को दिया। उन्होंने आगे कहा,

ष्लैवेंडर की खेती से किसानों की आय में काफी वृद्धि हुई है, जिससे उनकी कमाई लगभग 40,000–60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3,50,000–6,00,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से अधिक हो गई है।ष

चरक ने कहा कि लैवेंडर कम रखरखाव वाली, सूखा प्रतिरोधी और पशु–प्रतिरोधी फसल है, जो इसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाती है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम से रोपण के पहले दो वर्षों के बाद लगभग 15 वर्षों तक लाभ मिलता है।

कार्यक्रम का काफी विस्तार हुआ है, किसानों को 30 लाख से अधिक मुफ्त पौधे दिए गए हैं, और अब यह जम्मू–कश्मीर से आगे बढ़कर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर–पूर्वी राज्यों सहित भारत के अन्य हिस्सों तक फैल गया है।

जम्मू में वीजा...

तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान एकत्र साक्ष्यों के आधार पर सक्षम न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त किया गया, जिसके बाद आरएस पुरा के पुराना पिंड निवासी कार्तिक चौधरी के घर पर विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी की कार्रवाई नियमानुसार की गई और इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की गई।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी विदेश जाने के इच्छुक युवाओं को वर्क वीजा दिलाने का झांसा देता था। वह दावा करता था कि उसके पास विदेशों में नौकरी उपलब्ध कराने के लिए संपर्क और संसाधन हैं। इसी बहाने वह नौकरी चाहने वालों से मोटी रकम वसूल करता था। आरोप है कि आरएस पुरा क्षेत्र के कई निवासी उसके झांसे में आ गए और बेहतर रोजगार की उम्मीद में उसे पैसे दे दिए।

अधिकारी ने बताया कि शुरूआत में धोखाधड़ी की राशि अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन समय के साथ शिकायतों की संख्या बढ़ती गई और ठगी की कुल रकम में भी इजाफा होता गया। अब तक प्राप्त शिकायतों के अनुसार ठगी की राशि लगभग 90 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि कहीं इस मामले में अन्य लोग भी शामिल तो नहीं हैं, जो संगठित तरीके से युवाओं को निशाना बना रहे हों।

क्राइम ब्रांच ने बताया कि तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की बारीकी से जांच की जाएगी। बैंक खातों, लेन–देन और अन्य वित्तीय गतिविधियों की भी जांच की जा रही है ताकि ठगी की पूरी रकम और उसके उपयोग का पता लगाया जा सके। पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उपलब्ध साक्ष्यों को एकत्र कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अधिकारियों ने कहा कि युवाओं में विदेश जाकर रोजगार पाने की इच्छा का कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे मामलों में बिना किसी आधिकारिक अनुमति या वैध दस्तावेज के एजेंटों को पैसे देना गंभीर जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि विदेश जाने से पहले संबंधित एजेंसी या व्यक्ति की विश्वसनीयता की पूरी जांच करें और केवल अधिकृत माध्यमों से ही प्रक्रिया अपनाएं।

स्पेशल क्राइम विंग ने स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच जारी है। आगे और साक्ष्य जुटाने के साथ–साथ अपराध में शामिल अन्य संभावित व्यक्तियों की पहचान भी की जा रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

शराब न पीने वालों को भी क्यों होती है फैटी लिवर की प्रॉब्लम? ये है वजह

फैटी लिवर कई बार काफी गंभीर हो सकता है. इसका मुख्य कारण ज्यादा शराब का सेवन माना जाता है, लेकिन कई बार शराब न पीने वालों में भी फैटी लिवर की समस्या देखी जाती है. जानिए क्या है इसकी वजह?

फैटी लिवर जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में हेपेटिक स्टीटोसिस कहा जाता है. लिवर बॉडी से टॉक्सिन्स यानी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, इसलिए फैटी लिवर की समस्या पर वक्त रहते ध्यान देना बेहद जरूरी होता नहीं तो ये काफी गंभीर स्थिति में पहुंच सकती है और यह जानलेवा भी हो सकता है. पिछले कुछ सालों में फैटी लिवर के काफी केस देखे को मिले हैं. वहीं अक्सर यह सोचा जाता है कि फैटी लिवर की बीमारी सिर्फ उन लोगों को होती है जो शराब का सेवन करती हैं, हालांकि जो लोग शराब नहीं पीते हैं उन्हें भी फैटी लिवर की समस्या हो सकती है. दरअसल खराब खानपान भी फैटी लिवर होने की एक बड़ी वजह है.

एल्कोहॉलिक और नॉन एल्कोहोलिक, फैटी लिवर के ये दो प्रकार होते हैं. अगर बात करें एल्कोहॉलिक फैटी लिवर की तो इसमें ज्यादा अल्कोहल के सेवन से लिवर पर सूजन आ जाती है. वहीं नॉन एल्कोहॉलिक फैटी लिवर की समस्या के पीछे खराब खानपान हो सकता है. क्या होता है फैटी लिवर

लिवर में थोड़ी मात्रा में फैट पहले से मौजूद होता है, लेकिन जब शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है और यह फैट में तब्दील होकर लिवर की कोशिकाओं पर जमा होने लगता है तो यह स्थिति फैटी लिवर कहलाती है. जिससे लिवर के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है और पाचन भी खराब होने लगता है.

ये फूड हैं फैटी लिवर की वजह

ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट है जो ब्लड में मौजूद होता है और हमारा शरीर इस फैट का इस्तेमाल करके एनर्जी में तब्दील करता है, लेकिन इसकी अधिकता होने पर कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं.

इन्हीं में से एक हेल्थ प्रॉब्लम है फैटी लिवर. कुछ फूड्स जैसे वाइट ब्रेड, इंस्टेंट जंक फूड, कुकीज, रेड मीट, फ्राई फूड आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनमें सैचुरेटेड फैट होता है जो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की वजह है.

ये भी होता है फैटी लिवर होने का कारण शरीर के खून में ट्राइग्लिसराइड्स फैट बढ़ने से तो फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो ही सकती है. इसके साथ ही ज्यादा वजन बढ़ना और डायबिटीज से पीड़ित लोगों में भी फैटी लिवर की समस्या देखी जाती है.

लक्षणों को न करें इग्नोर

फैटी लिवर की समस्या होने पर अक्सर थकान महसूस होना, लिवर के हिस्से में त्वचा पर सूजन दिखाई देना, भारीपन महसूस होना, अक्सर उल्टी जैसा महसूस होना, खराब पाचन, भूख पर असर, वजन बढ़ना या फिर तेजी से वजन घटना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं.

प्रेगनेंसी में थकान से टूट रहा है शरीर, तो यह उपाय बन सकते हैं आपका सहारा

प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण वह सामान्य दिनों की तरह महसूस नहीं करती हैं। लेकिन कई बार यह सुस्ती और थकान आदि का असर आपके मूड पर भी पड़ता है। जिसकी वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है।

हर महिला के लिए मां बनने का एहसास इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। एक ओर जहां मां बनने का एहसास खुशी देता है, तो वहीं प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना होता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण वह सामान्य दिनों की तरह महसूस नहीं करती हैं। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी में आलस, थकान और सुस्ती ज्यादा लगती है।

इसी कारण प्रेगनेंसी का पता चलने पर डॉक्टर भी उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं। लेकिन कई बार यह सुस्ती और थकान आदि का असर आपके मूड पर भी पड़ता है। जिसकी वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है। अगर आपके साथ भी यह समस्या है तो बता दें कि यह आर्टिकल आपके लिए है। इस आर्टिकल के जरिए हम आपको 5 ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। जो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी सुस्ती और आलस को दूर भगाएंगे।

पानी ज्यादा पिएं

आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पेशाब ज्यादा लगती है। जिस कारण आमदिनों की अपेक्षा उनके शरीर में पानी की जरूरत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीती हैं, तो इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। यह मां और गर्भ में पलने वाले बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान लिक्विड डाइट बढ़ा देना चाहिए। इसलिए दिन में कम से कम 3/3.5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। लिक्विड डाइट के तौर पर आपको चाय, कॉफी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, एल्कोहल आदि का सेवन नहीं शुरू करना है। बल्कि लिक्विड डाइट में आप फलों का जूस, फलों की स्मूदी, सब्जियों की स्मूदी, नींबू पानी, दूध, शेक्स आदि पी सकती हैं।

मीठी चीजें कम खाएं

बता दें कि चीनी आपके शरीर में शुगर की मात्रा को अचानक से बढ़ा देती है। जिसकी वजह से आप थोड़े ही समय में थकान महसूस करने लगती हैं।

इसलिए गर्भावस्था के दौरान चीनी से बनी मीठी चीजों की सेवन कम से कम करना चाहिए। आप फल और ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं। क्योंकि इनमें प्राकृतिक मिठास पाई जाती है और यह आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। चीनी की जगह पर सिंपल कार्ब्स आपको ज्यादा समय तक एनर्जी से भरा रखेंगे।

अच्छी–गहरी नींद लें

प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का विकास होने के साथ ही पेट का वजन भी बढ़ने लगता है। तब सोने में समस्या होने लगती है। लेकिन बच्चे के पूर्ण विकास के लिए गहरी और अच्छी नींद लेना जरूरी होता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान सोने के समय आप प्रेगनेंसी पिलो का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

प्रेगनेंसी पिलो ऐसे तकिए होते हैं, जिससे आपको बंप के साथ सोने में परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा आप सोने के करीब एक घंटे पहले पानी पिएं। क्योंकि बाद में पानी पीने से रात में आपको पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है।

जरूर ले पावर नैप

प्रेगनेंसी के दौरान 7–8 घंटे की नींद आपको पूरादिन एक्टिव रखने के लिए काफी नहीं होती है। इसलिए आपके पास दिन में जब भी समय हो तो आप पावर नैप ले सकती हैं। पावर नैप यानी कि जब आप बोझिल महसूस करती हैं। तो दिन में आप 20–30 मिनट की नींद ले सकती हैं।

इससे आपको फिर से रिफ्रेशमेंट मिल जाती है। बता दें कि गर्भावस्था के दौरान नींद, खाना और पौष्टिक तत्वों की जरूरत दोगुनी हो जाती है।

रूटीन और समय करें फिक्स

गर्भावस्था के दौरान आपको अपने सोने, खाने, काम करने का समय और रूटीन फिक्स करना चाहिए।

इससे गर्भ में पलने वाले बच्चे का विकास बेहतर तरीके से होता है।

क्योंकि बेसमय का खाना और बेसमय की नींद आपके अंदर आलस, परेशानी और थकान को बढ़ाता है।

किन लोगों में हाई बीपी का खतरा ज्यादा रहता है, एक्सपर्ट से जानें

क्या आप जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर से न सिर्फ हार्ट बल्कि किडनी जैसा अहम अंग का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है. हाई ब्लड प्रेशर को मेडिकल में हाइपरटेंशन कहा जाता है जिसके होने पर हमारी नसों में रक्त का प्रवाह और ज्यादा हो जाता है. हेल्थलाइन के अनुसार हमारा नॉर्मल बीपी 120/80 एमजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर ये लेवल 140 से ज्यादा चला जाए तो इस कंडीशन में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक समेत कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

हाइपरटेंशन की समस्या किन लोगों को अधिक प्रभावित करती हैं हम आपको ये बताने जा रहे हैं. साथ ही जानें कि इसके लक्षण क्या है और इससे किस तरह बचाव किया जा सकता है.

हाइपरटेंशन के लक्षण

बहुत ज्यादा पसीना आना, बेहोशी महसूस होना, उल्टी–मतली, सिर और सीने में दर्द, सांस फूलना और आंखों में लाल निशान को हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण माना जाता है. हाई बीपी से दिल, दिमाग, किडनी और लिवर जैसे अहम अंगों के खराब होने का खतरा बना रहता है.

किन लोगों में हाई बीपी का खतरा ज्यादा रहता है

एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मोटापा और तनाव जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है तो उसे हाई बीपी हो सकता है. इसके अलावा बैलेंस डाइट न लेने वाले, शराब पीना, नींद की कमी और शारीरिक गतिविधि में कमी भी आपको हाई बीपी का मरीज बना सकती है.

किडनी भी होती है प्रभावित

गंगाराम हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. वैभव कुमार तिवारी के मुताबिक अगर किसी को लगातार हाई बीपी की समस्या रहती है तो इससे उसकी किडनी भी खराब हो सकती है.

एक्सपर्ट कहते हैं कि ब्लड प्रेशर के ज्यादा होने पर किडनी में मौजूद खून की नसों के डैमेज होने का रिस्क पैदा हो जाता है. किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती है और वेस्ट बाहर नहीं निकल पाता है. ब्लड में फ्लूइड के ज्यादा होने पर किडनी फेलियर भी हो सकता है.

ऐसे करें बचाव

हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर बीमारी है जिससे बचने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव बहुत जरूरी है. जीवनशैली को नियमित बनाने की आदत डालें.

स्मोकिंग या शराब से दूरी बनाए रखकर भी हाई बीपी से बचा जा सकता है.

व्यायाम या एक्सरसाइज के जरिए शरीर को फिट रखने की कोशिश करें.

शशारीरिक गतिविधियों के जरिए एक्टिव रहने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है.

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

समानता बनाम मनुवाद : यूजीसी नियमावली और जाति वर्चस्व का प्रतिरोध

विक्रम सिंह

जाति प्रथा कितनी घृणित और अमानवीय है, यह हमारे देश में बताने की ज़रूरत नहीं है। दलितों पर रोज़ होने वाले अमानवीय अत्याचार और उनके साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार, इसकी चीख–चीख कर गवाही देते हैं। लेकिन जब जाति व्यवस्था को मनुवादी विचारधारा का राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है, तो जाति व्यवस्था कितनी उग्र, आक्रामक और खुले रूप में सामने आती है, यह हमने पिछले कुछ हफ़्तों में साफ़ तौर पर देखा है। जनवरी महीने में मीडिया और सोशल मीडिया में ऐसा दिखाया जा रहा था, जैसे देश में कोई बहुत बड़ा सामाजिक संकट आ गया हो। पूरे देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के संवर्धन हेतु), के तहत जारी नियमावली का तीखा विरोध हुआ। तथाकथित उच्च जातियों के नौजवान ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जैसे उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। हालांकि विरोध करने वाले संख्या में कम थे लेकिन उनके विरोध का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। इसका कारण यह है कि शक्ति के केंद्र में उनकी पहुँच ज्यादा है। नीति–निर्धारण करने वाले स्थानों पर बैठे लोग उनके साथ ही खड़े होते हैं। केवल यही तथ्य कि कम लोगो के विरोध का अधिक प्रभाव और असर हुआ है, न्ळब द्वारा जारी नई नियमावली की सार्थकता और ज़रूरत को न्यायोचित ठहराता है। यह देश में विद्यमान अमानवीय जाति प्रथा का परिणाम है।

'समानता से घबराहटरू असुरक्षा नहीं, श्रेष्ठता पर चोट'

कितना विचित्र है कि यह विरोध एक ऐसे प्रयास का हो रहा है, जिसका मकसद ही भेदभाव को रो. कना है। हालांकि यह समझना ज्यादा जरुरी है कि यह कदम भी बहुत ढीला ढाला और अनमना है। लेकिन फिर भी इतना घोर विरोध? क्या समानता के लिए प्रयास करना हमारे समाज में इतना बुरा हो गया है। यह पूरा प्रकरण दरअसल उच्च जातियों की असुरक्षा का मसला ही नहीं है। इसका तो केवल हवाला देकर आन्दोलित, यूं कहें तो आक्रोशित किया गया है नौजवानों को। असल कारण तो है जाति श्रेष्ठता को मिल रही चुनौती को ख़ारिज करना। डर यह नहीं है कि इस नियमावली के तहत गलत शिकायतें दर्ज होंगी, लेकिन डर यह था कि शिकायतें दर्ज होंगी। शिकायतें दर्ज होंगी समानता को जार–जार करने वाले मनुवादी विचार के वाहकों के खिलाफ, जो इंसानों में भेदभाव करना अपना हक़ समझते है। चिंता तो असल यह थी कि समानता का पाठ पढ़ाने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में खुले में चल रहे सर्वमान्य भेदभाव और गैर–बराबरी के खिलाफ कमजोर ही सही, आवाज उठाने की कुछ ताकत यह नियमावली देती है।

हालांकि अगर इस पूरे विरोध अभियान की भाषा और शैली को देखे तो साफ हो जाता है कि देश में राजनीतिक तौर पर मनुवाद कितना हावी हो गया है। विरोध करने वाले बड़ी ही आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करे रहे थे और खुले तौर पर जातिसूचक शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे। मीडिया की कवरेज भी जातीय समझ से ग्रसित और पूरी तरह एकपक्षीय थी। ऐसा दिखाया जा रहा था मानो इस नियमावली से हिन्दू समाज विभाजित हो जाएगा और जैसे इससे अगड़ी जातियों के लोग बेचारे बन जाएंगे। पूर्वाग्रह से ग्रसित मीडिया ने तो यह तक घोषित कर दिया कि इस नियमावली का दुरुपयोग ही होगा। एक चौनल के एंकर ने एक पैनलिस्ट से यहाँ तक कह दिया कि यदि मैं कुछ सवाल पूछ लूँ, तो कहीं आप मुझ पर एससी/एसटी एक्ट न लगा दें। जब उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगाई, तो कई चौनलों ने इसे पंडितों और क्षत्रियों की जीत घोषित किया और कहा कि यह देश को बाँटने वालों की हार है।

'यूजीसी नियमावली की संरचना रू क्या है प्रस्ताव और उसका उद्देश्य?'

अभी तक यूजीसी की नियमावली पर खूब चर्चा हो चुकी है। 15 जनवरी से लागू की गई (जिस पर अब उच्चतम न्यायलय ने रोक लगा दी है) इस नियमावली के अनुसार प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को समान अवसर केंद्र का गठन करना अनिवार्य किया गया है, जिसका मकसद सब के लिए सामान अवसर उपलब्ध करवाना है। इस केंद्र के कार्य संचालन का प्रबंधन करने तथा भेदभाव से संबंधित शिकायतों की जाँच करने के लिए एक समानता समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी संरचना इस प्रकार होगी रू शिक्षण संस्थान के प्रमुख इसके पदेन अध्यक्ष होंगे ; उच्च शिक्षा संस्थान के तीन प्रोफेसर/वरिष्ठ संकाय सदस्य इसके सदस्य होंगे ; एक गैर शिक्षण कर्मचारी सदस्य होगा ; प्रासंगिक अनुभव वाले नागरिक समाज के दो प्रतिनिधि सदस्य होंगे ; शैक्षणिक योग्यता/खेल उपलब्धि/सह–पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर नामित किए जाने वाले दो छात्र प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे ; तथा समान अवसर केंद्र के समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे, और समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजा. ति तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से होगा।

यह समिति वर्ष में दो बार अपनी बैठक करेगी और प्रत्येक छह माह में अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी, जिसमें जाति–आधारित ड्रॉपआउट (बीच में पढ़ाई छोड़ने) की दर, प्राप्त कुल शिकायतों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण शामिल होगा ; साथ ही 24 घंटे कार्यरत एक हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, प्रत्येक छात्रावास और विभाग में इक्विटी स्क्वाड का गठन किया जाएगा तथा इक्विटी एम्बेसडर नियुक्त किए जाएंगे, जिनका दायित्व त्वरित हस्तक्षेप करना और जागरूकता फैलाना होगा ; किसी भी शिकायत के प्राप्त होते ही 24 घंटे के भीतर समिति की बैठक बुलाना अनिवार्य होगा और उस पर निर्धारित समय–सीमा के भीतर कार्यवाही करनी होगी ; कार्यवाही की पर्याप्तता या अपर्याप्तता के संबंध में अपील के लिए एक निष्पक्ष लोकपाल (ओम्बुड्समैन) की व्यवस्था होगी।

'नियमावली की सीमाएँ और गंभीर खामियां'

हालांकि इस गाइडलाइन्स में कई कमियां है, जैसे यह भेदभाव की कोई साफ़ और पूरी परिभाषा नहीं देते हैं। इनमें ज़्यादा ज़ोर सिर्फ़ यह दिखाने पर है कि भेदभाव नहीं है, जबकि उच्च शिक्षा संस्थानों में मौजूद असली और रोज़मर्रा के भेदभाव के अनुभवों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। ज़रूरी है कि इस ढाँचे को और मज़बूत बनाया जाए, ताकि छात्रों और शिक्षकों को जिन–जिन तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उन्हें साफ़ तौर पर माना जाए, समझाया जाए, पहचाना जाए और उन्हें खत्म किया जा सके। एक बड़ी कमजोरी यह है कि समानता समिति (इक्विटी कमेटी) का गठन किसी संस्थान प्रमुख की इच्छा और मनमर्जी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि उसकी विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए छात्रों, शिक्षकों और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह गाइडलाइन्स केवल विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों तक ही सीमित हैं और आईआईटी, आईआईएम, एम्स तथा ऐसे अन्य केंद्रीय संस्थानों पर लागू नहीं होते, जो एक गंभीर कमी है ; सरकार को इस खामी को दूर करते हुए इन संस्थानों तक भी प्रभावी समानता तंत्र का विस्तार करना चाहिए। यूजीसी ने समानता समिति के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों के निपटारे के लिए ओम्बड्सपर्सन नियुक्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित कर लिया है, जबकि चूँकि बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों के तहत स्थापित हैं, इसलिए संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों के अनुरूप ओम्बड्सपर्सन की नियुक्ति का अधिकार संबंधित राज्य सरकारों के पास होना चाहिए।

'आंदोलनों की विरासत'

लेकिन इसके बावजूद एक लम्बे आंदोलन के बाद इस पड़ाव पर पहुंचना महत्वपूर्ण है। यह नियमावली कोई सरकार की वंचित तबकों की शिक्षा और शिक्षण संस्थानों में उनकी बदतर हालत की कोई चिंता से नहीं उपजी है, बल्कि पिछले एक दशक में श्रेष्टता पर आधारित मनुवादी वैचारिकी वाली भाजपा सरकार का शासन वंचित समुदायों, विशेष तौर पर दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यंकों के खिलाफ हिंसक वातावरण पैदा करने वाला ही रहा है। इस नियमावली को लाने के पीछे आंदोलनों का एक लम्बा इतिहास रहा है, जो शुरू हुआ था हैदराबाद विश्वविद्यालय के रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या के खिलाफ न्याय के लिए शुरू हुए आंदोलन से। उस समय पूरे देश का छात्र समुदाय सडकों पर उतर आया था। लेकिन ऐसी घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस बीच 26 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर पायल तड़वी ने 2019 में मुंबई के बीवाईएल नायर अस्पताल में जातिगत भेदभाव और वरिष्ठ सहकर्मियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। हालाँकि वर्ष 2012 में यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव दिशा–निर्देश जारी किये थे, लेकिन रोहित वेमुला, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी की दुखद मौतों से यह साबित होता है कि 2012 की यूजीसी दिशानिर्देश वास्तव में कितने खोखले और अप्रभावी थे। साथ ही यह मौतें देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जड़ जमाए जातिगत उत्पीड़न की सच्चाई को निर्ममता से उजागर करते है।

रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताएं (क्रमशः राधिका वेमुला और आबेदा सलीम तड़वी) इस आन्दोलन को अदालत में ले गई और 2019 में एक जनहित याचिका दायर की। इस जनहित याचिका में परिसरों में जाति–आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक प्रभावी तंत्र की मांग की गई थी। इस याचिका के तहत मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि यूजीसी ने याचिका में उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रारूप विनियम तैयार कर लिए हैं। अप्रैल में अदालत ने स्पष्ट किया कि यूजीसी प्रारूप विनियमों को अंतिम रूप देकर अधिसूचित कर सकती है। अंतता सितंबर महीने में अदालत ने यूजीसी को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने और विनियमों की अधिसूचना के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया। इस प्रक्रिया का ही परिणाम है श्प्रमा. `शन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंसश।

'बराबरी बनाम विभाजन रू असली सवाल क्या है?'

अब यह देखना बहुत रोचक है कि जब न्याय के लिए कानूनी लड़ाई के बाद न्यायालय के हस्तक्षेप से ही यह नियमावली बनी और अदालत ने इसके महत्व पर टिप्पणी भी की, फिर उच्चतम न्यायालय ने ही इस पर रोक लगा दी। न केवल अस्थाई रोक लगा दी, बल्कि त्वरित सुनवाई भी की। उतना ही खेदजनक है न्यायालय की टिप्पणी। इस पर रोक लगाते हुए सीजेआई ने इन नियमों को श्समाज को बांटने वालाश और श्पीछे ले जाने वालाश बताया। प्रश्न तो यह है कि न्यायालय किस समाज को बांटने की बात कर रहा है, जो पहले से जातियों में न केवल बंटा है, बल्कि अन्यायपूर्ण तरीके से श्रेणीकृत भी है, जहां तथाकथित अगड़ी जातियां दलितों और आदिवा. सियों को प्रतिदिन उनकी दोयम स्थिति का आभास करवाती है।

यह केवल सच्चाई से आँखें मूंदने का मामला नहीं है, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था में व्याप्त जाति का भी परिचायक है। हमारी अदालतों में अक्सर जाति का मजाक बनाया जाता है और न्याय व्यवस्था में विद्यमान जाति–आधारित भेदभाव के कई प्रमाण उपलब्ध हैं। यहां केवल दो उदाहरण काफी है। 2001 में एक 30–सदस्यीय संसदीय समिति और 2014 में अनुसूचित जाति आयोग ने अपनी–अपनी रिपोर्टों में यह पुष्टि की कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भारतीय न्यायाधीशों में जातिगत पूर्वाग्रह मौजूद हैं, जो केवल उनकी सोच तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनके न्यायिक फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। इन दोनों रिपोर्टों में न्यायिक व्यवस्था के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ विभिन्न प्रकार के जातिगत भेदभाव को दर्ज किया गया था, जबकि अक्टूबर 2021 में अमेरिकन

■ शेष पेज 5...

■ शेष पेज 4 से...

बार एसोसिएशन के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट ने दलित वकीलों के साथ हो रहे अप्रत्यक्ष भेदभाव को रेखांकित किया, जिसमें उन्हें अच्छे ऑफिस न दिए जाना, सीनियर काउंसिल द्वारा कम वेतन देना, कार्यस्थल पर बुलिंग करना या उनसे निम्न स्तर के काम करवाना जैसे व्यवहार शामिल हैं।

जब अदालतें भी जातीय उत्पीड़न से नहीं बची हैं, तो हमारे माननीय किस समाज को बाँटने की बात कर रहे है? यह एक नया तरीका है कि भेदभाव को अस्वीकार ही कर दो। यही तो आधार है पूरे देश में इस नियमावली के विरोध का। अगर समाज को बराबरी पर लाना है और एकता स्थापित करनी है, तो पहले से व्याप्त असमानता को स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ लड़ने के उपाय करने होंगे। यह महत्वपूर्ण पक्ष हमारे संविधान ने स्वीकार किया था और उसके अनुसार ही उपाय भी सुझाये थे।

'आँकड़े आईना दिखाते हैं'

गौरतलब है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में लगातार बढ़ रहे अत्याचार के मामले अदालत के रुख को आईना दिखाते है। यूजीसी द्वारा संसदीय समिति और सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति–आधारित भेदभाव की शिकायतों में पिछले पाँच वर्षों में 118.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के आंकड़े यह भी पुष्टि करते हैं कि जातिगत भेदभाव की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही संकाय सदस्यों में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व घटता जा रहा है, जहां अनुसूचित जाति का नामांकन 14 प्रतिशत से घटकर केवल 6 प्रतिशत रह गया है, जो संस्थागत स्तर पर बढ़ते बहिष्करण की ओर इशारा करता है।

देश की राजधानी दिल्ली स्थित डॉ. बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय में जाति के आधार पर हो रही रैगिंग के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले छात्र संघ के सदस्यों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर से निष्कासित कर दिया। यह वही छात्र संघ है, जिसे छात्रों ने लोकतांत्रिक तरीके से ठीक इसी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए चुना था। इन छात्रों का तथाकथित 'अपराध' सिर्फ़ इतना था कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दलित छात्रों के खिलाफ उनकी जाति के आधार पर हो रही रैगिंग का विरोध किया और प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लेकिन प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय छात्र संघ के सदस्यों को ही दंडित कर दिया।

'मनुवादी वर्चस्व और राज्य सत्ता का गठजोड़'

विरोध करने वाले लोग एक बेहद बेढंगे और भ्रामक तर्क के साथ यह कह रहे थे कि उनकी जाति का नाम उन समूहों में शामिल नहीं है, जिनके खिलाफ भेदभाव हो सकता है। वे चाहते हैं कि इस नियमावली में उन जातियों और समूहों को भी शामिल किया जाए, जो भेदभाव के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह तर्क दरअसल देश में मौजूद जाति व्यवस्था और उसके गहरे सामाजिक प्रभावों को नकारने की एक कोशिश है। यह सवाल ठीक वैसा ही है, जैसे यह पूछा जाए कि महिला उत्पीड़न रोकने के लिए बने वुमन सेल में पुरुषों को क्यों शामिल नहीं किया गया। वजह बिल्कुल साफ़ है, जातिगत उत्पीड़न की संरचना ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ निर्मित हुई है। इसे स्वीकार करना किसी का बहिष्कार नहीं, बल्कि उस असमान यथार्थ को मान्यता देना है, जिसे सदियों से 'सामान्य' बनाकर स्वीकार किया जाता रहा है।

दूसरी बड़ी हाय–तौबा मचाई जा रही है कि इसका तथाकथित दुरुपयोग होने की संभावना पर। यह पहली बार नहीं है। जब भी समाज में भेदभाव को रोकने के लिए कोई प्रावधान लाया जाता है, तो भेदभाव करने वाले लोग तुरंत इसके दुरुपयोग की बात करने लगते हैं। यही तर्क और प्रचार हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को लेकर भी देखा है। यह नियम किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस व्यवस्था को चुनौती देता है, जिसने जातिगत असमानता को अब तक 'नॉर्मल' बना रखा था। कैंपस में समता भाषणों से नहीं, बल्कि सख्त, जवाबदेह और लागू होने वाले नियमों से आएगी।

हमारे अनुभव भी है कि कैसे हमारा समाज इस असरदार कानून को भी अपने जातीय प्रभाव से बेअसर कर देता है।

हमने देखा है, मुक़दमा दर्ज होने के बाद भी न्याय लगभग असंभव हो जाता है वंचित तबकों के लिए। उल्टा अदालत की कार्यवाही पीड़ित के लिए ही दंड बन जाती है और आरोपी छूट जाते है। हाथरस गैंग रेप केस इसका सबसे जीता–जागता उदाहरण है। फिर कम दोषसिद्धि दर होने का हवाला देकर इस कानून के दुरूपयोग की बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया।

आज के समय में तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को संसद में पास करवाना संभव नहीं होता। इसके खिलाफ सरकार की सुरक्षा में देश की दमनकारियों व वर्चस्व वाली जातियों की मज़बूत लामबंदी हो जाती, जैसा कि यूजीसी की गाइडलाइन्स के बारे में हुआ है। यह अपने आप नहीं हुआ है, बल्कि यह आरएसएस के नेतृत्व में भाजपा के शासन का एक परिणाम है। यह आरएसएस के मनुवादी एजेंडे का मजबूत होना है।

'न्याय और समानता के लिए निर्णायक संघर्ष की ज़रूरत'

यूजीसी की यह नियमावली किसी समाज को बाँटने का औज़ार नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक अन्याय को चुनौती देने का प्रयास है, जिसे सदियों से 'सामान्य' बनाकर स्वीकार कर लिया गया है। बराबरी की बात करना अगर आज भी 'विभाजन' कहलाता है, तो यह हमारे लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था और सामाजिक चेतना पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न है।

जाति–आधारित उत्पीड़न को नकारना, उसके खिलाफ बने न्यूनतम संरक्षणों को भी ख़तरा बताना और हर प्रयास को 'दुरुपयोग' के भय से खारिज कर देना, असल में उसी मनुवादी व्यवस्था की रक्षा है, जो असमानता से पोषित होती है। अनगिनत नामहीन पीड़ितों की स्मृतियाँ हमसे यह सवाल करती हैं कि क्या हम बराबरी को सिर्फ़ संवैधानिक शब्दों में सीमित रखेंगे या उसे संस्थानों की ज़मीन पर उतारने का साहस भी करेंगे।

अगर सचमुच एक समतामूलक, लोकतांत्रिक और एकजुट समाज बनाना है, तो पहले यह स्वीकार करना होगा कि समाज पहले से बँटा हुआ है और उसे जोड़ने का रास्ता केवल न्याय, जवाबदेही और समानता से होकर ही जाता है। इसलिए न्यायालय को उपरोक्त नियमावली में मौजूद कमियों के दूर कर, ज्यादा मज़बूत और प्रभावशाली गाइडलाइन्स लागू करनी चाहिए। देश के प्रगतिशील जनता के सामने भी यह ठोस सवाल है कि मनुवादी सोच की जीत होगी या सभी तरह भेदभाव को ख़त्म कर समतामूलक सोच को लागू करने के लिए देश निर्णायक लड़ाई में आगे बढ़ेगा।

'(लेखक एसएफआई के पूर्व महासचिव और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त सचिव हैं। संपर्क रू 9418484418)'

एआई कैसे बदल सकता है भारत के किसानों की तकदीर?

अन्नपूर्णा देवी

भारत में अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा सिर्फ नई तकनीक के रूप में नहीं हो रही है। ध्यान इस बात पर जा रहा है कि एआई आम लोगों की असली समस्याएँ कैसे हल कर सकता है। खेती और खाद्य क्षेत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ समस्याएँ छोटी नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से जुड़ी हैं। यहाँ कोई भी तकनीक तभी सफल होगी जब वह मौसम, ढुलाई और बाज़ार जैसी स्थानीय परिस्थितियों को समझे।

भारत इतना भोजन पैदा करता है कि पूरी आबादी का पेट भर सके, फिर भी हर साल करीब 6.8 करोड़ टन खाना बर्बाद हो जाता है। कटाई के बाद 35 से 40 प्रतिशत फल और सब्जियाँ खराब हो जाती हैं। यह समस्या उत्पादन की कमी की नहीं, बल्कि सही समय पर सही जानकारी और बेहतर व्यवस्था न होने की है। यानी खेत से बाज़ार तक तालमेल की कमी है और फैसले समय पर नहीं हो पाते। ऐसे में भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया एआई इस नुकसान को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।

क्यूज़ेंस लैब्स में हमने इस बात पर गौर किया कि भारत की डिजिटल व्यवस्था ने भुगतान, पहचान और सेवाओं को बदल दिया है, लेकिन खाने के क्षेत्र में गुणवत्ता की जाँच अब भी पुराने तरीकों से होती है। इसी सोच के साथ हमने फैबंद नाम की एआई तकनीक विकसित की, जो इन्फ्रारेड तकनीक और कृत्रिम सूंघने की मदद से फल–सब्जियों की अंदर की गुणवत्ता पहचानकर तुरंत काम आने वाली जानकारी देती है। उदाहरण के तौर पर कोई फल या सब्जी कितने दिन तक चल सकती है कितने दिन स्टोर कर सकते हैं इत्यादि। इसका मकसद कम मुनाफे पर काम करने वाले किसानों, दुकानदारों और ग्राहकों की उलझन कम करना है।

अनुभव बताते हैं कि एआई तभी सफल होगा जब वह भारत की वास्तविक परिस्थितियों को समझे। विदेशों के डेटा पर बने मॉडल भारत जैसे विविध देश में अक्सर सही काम नहीं करते, क्योंकि हर क्षेत्र में फसल, मौसम, भंडारण और बाज़ार अलग हैं। अगर एआई भारतीय हालात को नहीं समझेगा, तो वह बेकार साबित हो सकता है या गलत नतीजे भी दे सकता है।

इसी कारण स्वदेशी एआई पर जोर देना समय की जरूरत है। सरकार की प्दकपं।प् डपेपवद पहल दिखाती है कि अब एआई को सिर्फ उन्नत तकनीक नहीं, बल्कि देश के विकास का जरूरी साधन माना जा रहा है।

भारतीय डेटा, देश में बने समाधान और अलग–अलग क्षेत्रों के लिए खास तकनीक को बढ़ावा देकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जहाँ नवाचार सीधे लोगों की जरूरतों से जुड़ा हो।

खाद्य और खेती का क्षेत्र बताता है कि यह क्यों जरूरी है। अगर कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम हो जाए, तो किसानों की आय बढ़ेगी, खाने की कीमतें स्थिर रहेंगी और पानी, जमीन और ऊर्जा की बचत होगी।

इससे पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा और पूरी व्यवस्था ज्यादा मजबूत बनेगी। एक और जरूरी पहलू है सबकी भागीदारी। एआई ऐसा होना चाहिए जो छोटे किसानों, स्थानीय भाषाओं और छोटे बाज़ारों में भी आसानी से काम कर सके।

जो तकनीक लोगों पर फैसले थोपेगी, उस पर भरोसा नहीं बनेगा। लेकिन जो तकनीक छिपी जानकारी को आसान तरीके से सामने लाकर बेहतर फैसले लेने में मदद करेगी, वही लंबे समय तक टिकेगी और फैल सकेगी।

16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में होने वाला भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब दुनिया एआई के असर पर गंभीर चर्चा कर रही है।

भारत के पास मौका है कि वह ऐसा रास्ता दिखाए जहाँ एआई आम लोगों के काम आए, स्थानीय जरूरतों को समझे और असली आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हो।

खेती, खाद्य आपूर्ति और जलवायु से जुड़ी चुनौतियाँ इस दिशा के केंद्र में हैं।

यह भी समझना जरूरी है कि एआई अपने–आप बदलाव नहीं लाता।

इसके लिए सही समझ, सही नीति और मिलकर काम करना पड़ता है। लेकिन जब इसे सही तरीके से अपनाया जाता है, तो यह बिना शोर किए बड़े बदलाव ला सकता है।

इम्पैक्ट समिट के मद्देनजर असली चुनौती एआई को तेजी से अपनाने की नहीं, बल्कि सोच–समझकर सही जगह इस्तेमाल करने की है। आखिर में सफलता का असली पैमाना यही होना चाहिए कि क्या एआई से भोजन की बर्बादी कम होती है, क्या किसानों की आय बढ़ती है और क्या देश की व्यवस्था मजबूत होती है।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

3000 चीनी सैनिक से भिड़ गए भारत के 120 जवान, जब 18 हजार फीट की ऊंचाई पर हुई बॉर्डर फिल्म जैसी लड़ाई

ये 1962 के भारत और चीन युद्ध के साथ जुड़ी है। इसमें भी वीरता की तमाम मिसालें हैं जिन्हें सुना जाना चाहिए था, सुनाया जाना चाहिए था और दुनिया को बताया जाना चाहिए था। लेकिन उन्हें उस तरह से नहीं बताया गया जिस तरह से उनका उस युद्ध में योगदान था। इस जंग में शामिल कई भारतीय जवानों के पार्थिव शव बर्फ में दबे मिले थे।

अभिनय आकाश

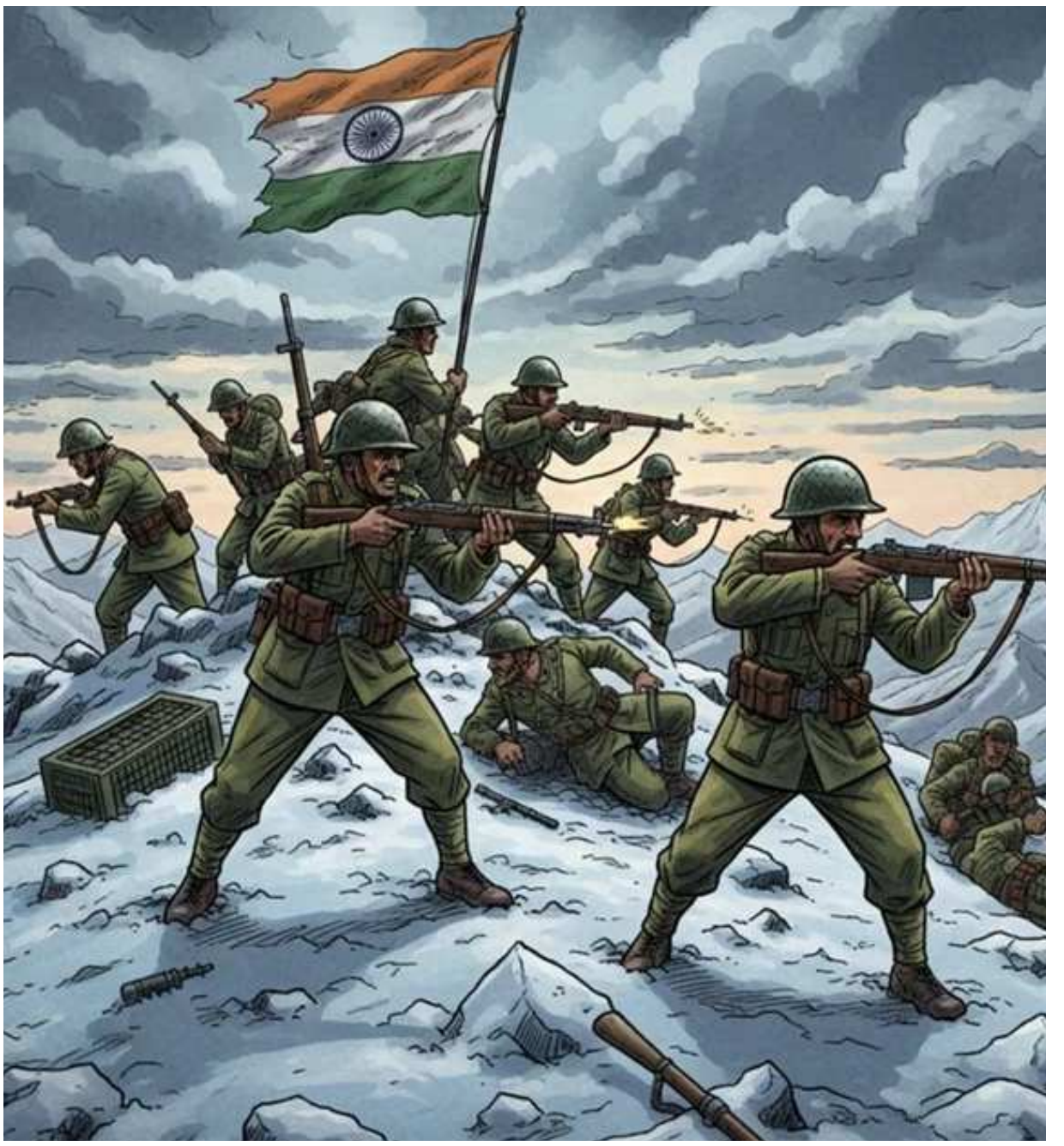

बहुत से लोग बगैर लड़ाई लड़े ही रिटायर हो जाते हैं। लेकिन कुछ चुने हुए लोगों को भारत माता अपनी सेवा करने का मौका देती है। इस बार भारत माता ने अपनी रक्षा के लिए हमें चुना है। चीन सोच रहा है कि जैसे बीस अक्टूबर को उसने दगाबाजी ने हमारी जमीन छीन ली है वैसे ही अब वो चुशूल भी छीन लेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि यहां कौन बैठा है। 13 कुमाऊं के बहादुरों अब दुश्मन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है।ष 11 नवंबर 1962 के दिन ठीक सुबह 10 बजे लेफ्टिनेंट कर्नल एचएस ढींगरा के ये जोश भरे शब्द लद्दाख की बर्फिली वादियों में गूंज रहे थे। इस वक्त तक चीन से लड़ाई छिड़े 20 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। लेफ्टिनेंट कर्नल एचएस ढींगरा के संबोधन के बाद भारतीय सेना के जवानों ने चीन के खिलाफ असाधारण वीरता का परिचय दिया। कोई भी जंग होती है और उस जंग में जब जीत होती है, तो उसकी कहानियां, उसकी वीरता की कहानियां , शहादत के किस्से कई दशकों तक सुने सुनाए जाते हैं। लेकिन अगर किसी जंग में हार हो जाती है तो उस हार की वजहों वाली फाइल के साथ ही वैसी कहानियों को भी दफन कर दिया जाता है। एक ऐसी ही कहानी रेजांग ला की भी है। ये 1962 के भारत और चीन युद्ध के साथ जुड़ी है। इसमें भी वीरता की तमाम मिसालें हैं जिन्हें सुना जाना चाहिए था, सुनाया जाना चाहिए था और दुनिया को बताया जाना चाहिए था। लेकिन उन्हें उस तरह से नहीं बताया गया जिस तरह से उनका उस युद्ध में योगदान था। इस जंग में शामिल कई भारतीय जवानों के पार्थिव शव बर्फ में दबे मिले थे। वो भी तीन महीने बाद। इन जवानों के पार्थिव शवों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अभी भी दुश्मनों से मोर्चा लिए हुए हैं।

भेड़ों को चराते चराते भटकता हुआ गड़ेरिया पहुंचा रेजांगला

बात फरवरी 1963 की है। चीन से लड़ाई खत्म होने के तीन महीने बाद लद्दाख का एक गड़ेरिया अपनी भेडों को चराते चराते भटकता हुआ चुशूल से रेजांगला जा पहुचा। एकदम से उसकी निगाह तबाह हुए बंकरों और इस्तेमाल की गई गोलियों के खोलों पर पड़ी। वो और पास गया तो उसने देखा कि वहां चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। वर्दी वाले सैनिकों की लाशें। नर्सिंग असिस्टेंट के हाथ में सिरिंच था, किसी की राइफल आगे से उड़ चुकी थी पर उसका बट उनके हात में ही था। इस तरह की लाशें मिली जिससे तब पता चला कि ये लोग कितनी बहादुरी से लड़े थे। गड़ेरिया वापस आया, उसने अधिकारियों को जानकारी दी। हालाँकि रेजांगला से लौटे कुछ जवानों ने पहले भी ये कहानी सुनाई थी कि रेजांगला में क्या हुआ, लेकिन तब किसी ने उनकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया था। 124 सैनिकों ने चीन की 3000 की फोज को रोक दिया था। सुनने में असंभव लगता था। ये असंभव संभाव कैसे हुआ?

18 नवंबर 1962 को क्या हुआ था

सुबह होने को थी, बर्फीला धुंआ का पसरा हुआ था। सूरज 17,000 फीट की उचाई तक अभी नहीं चढ़ पाया था। लद्दाख में ठंडी और कलेजा जमा देने वाली हवाएं चल रही थी। यहां सीमा पर भारत से प्रहरी मौजूज थे। 13 कुमाओं बटालियन की सी कंपनी चुषूल सेक्टर में तैनात थी। सुबह के धुन्दल के पर रिजांगला यानी रिजांगला के पास पर चीन की तरफ से कुछ हलचल शुरू हुई। बटालियन के जवानों ने देखा कि उनकी तरफ रोशनी के कुछ गोले चले आ रहे हैं। बटालियन के अगुआ मेजर शैतान सिंह थे, उन्होंने गोली चलाने के आदेश दे दिये। थोड़ी देर बाद मेजर शैतान सिंह को पता चला कि ये रोशनी के गोले असल में लालटेन हैं। इन्हें कई सारे यार्क के गले में लटका कर चीन के सेना ने इन्हें भारत की तरफ भेजा था। ये एक चाल थी भारतिय फौज को चकमा देने की। भारतीय फौज के पास हथियार सीमित थे। बंदूके भी ऐसी जो एक बार में एक फायर कर पाती थी। इतने हथियारों के साथ रिजांगला को बचाना था। इसके अलावा इन सैनिकों को इतनी हाइट पर लडने का अनुभव भी नहीं था। 13 कुमाऊं की बटालियन को सीधे कश्मीर से चुषूल भेजा गया था ताकि वहां मौझूद हवाई पट्टी को बचाया जा सके। इतनी उचाई तक आने के लिए कोई रोड नहीं था। रसद पहुचांने का एक मात्र तरीका हवाई जहाज था। 18,000 फीट की उचाई पर पढ़ने वाली थंड से बचने के लिए सैनिक पूरी तरह तैयार नहीं थे। अधिकतर जवान हरियाणा से थे, जिन्होंने अपनी जिन्दगी में बर्फ पहले कभी नहीं देखी थी। न ढंग के कपड़े थे, न ही बर्फ के जूते। कुछ तो ट्रेनिंग कर रहे थे, वहां से लाए गए 18–19 साल के इन लड़कों को सीधे चुषूल भेजा गया था। बहुत कुछ था जो नहीं था, लेकिन एक चीज की कोई कमी नहीं थी और वो थी जोश, जो उन्हें अपने लीडर मेजर शैतान सिंह से भरपूर मिल रहा था।

बटालियन ने अपने मेजर के फैसले पर भरोसा दिखाया

18 नवंबर को जब लड़ाई शुरू हुई, मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को पहाड़ी के सामने की ढलान पर तैनात किया। उनकी पोजीशंस बेहतर थी क्योंकि चीन का हमला नीचे से उपर की ओर होना था। हलांकि चीनी सेना पूरी तयारी से आई थी, उन्हें ठंड में लड़ने की आदत भी थी और उनके पास पर्याप्त हथियार भी थे। हमले के पहले दौर में भारतीय फौज ने चीनियों को पीछे खदेडा। लेकिन शैतान सिंह जानते थे कि चीनी फौज उनका गोला बारूद खत्म होने का इंतजार कर रही है। उन्होंने वायलेस पर सीनियर अधिकारियों से बात की, मदद मांगी। सीनियर अफिसर्स ने कहा कि अभी मदद नहीं पहुंच सकती। आप चाहें तो चौकी छोड़कर पीछे हट सकते हैं, अपने साथियों के जान बचाईए मेजर इसके लिए लेकिन तैयार नहीं हुए। चौकी छोड़ने का मतलब था हार मानना। उन्होंने अपनी टुकडी के साथ एक छोटी सी मीटिंग की, सिच्वेशन की ब्रीफिंग दी। कहा कि अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो हट सकता है लेकिन मैं लड़ रहा हूँ और मेरे साथ जो लोग रुकेंगे वो भी लड़ेंगे। गोलियां कम थी, ठंड की वजह से उनका शरीर जबाब दे रहा था और चीन से लड़ पाना नामुंकिन सा था। लेकिन बटालियन ने अपने मेजर के फैसले पर भरोसा दिखाया। तो जवानों ने आपस में डिसकस करके बोला कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, यही मैं आगे फॉर्वर्ड कर रहा हूँ कि लास्ट मैन लास्ट बुलेट तक लड़ेंगे लेकिन इसके बाद अगर कोई भी पीछे मुड़ेगा तो मैं उसको गोली से मार दूँगा। फिर थोड़ी देर रूक कर कहा कि उन्होंने बोला कि अगर मैं मुड़ता हूँ तो मैं आज आपको परमिशन दे रहा हूँ कि आप मुझे गोली मार देना।

रेजांग ला के युद्ध में क्या हुआ था?

उस वक्त उनकी पूरी रेजीमेंट ने पोस्ट पर डटे रहने का फैसला किया था और युद्ध में जाबांजी दिखाते हुए चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोका था। चीनी सैनिकों ने किस्तों में हमला किया, उनके पास मशीनगन था, जबकि भारतीय सैनिक राइफल से युद्ध लड़ रहे थे, वे संख्या में 3000 थे और भारतीय 120। बावजूद इसके मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 जांबाजों ने जान लड़ा दिया और 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को मारा। उनके हमलों को नाकाम करते हुए वे तबतक लड़े जबतक उनके शरीर में जान रही। मेजर शैतान सिंह ने तो दोनों हाथ जख्मी होने के बाद अपने पैरों से गन चलाया और दुश्मनों को मारा. मेजर शैतान सिंह को हमले से बचाकर रखने वाले सैनिक ने उनकी लाश को बर्फ में दबा दिया था। इस युद्ध के लड़ाकों ने हथियार और गोली–बारूद समाप्त हो जाने के बाद अपने हाथों और मेजर ने उससे कहा था तुम चले जाओ और जाकर सबको बताओ कि 13 कुमाऊं रेजीमेंट के लड़ाकों ने कैसे युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में कुछ को चीनी सैनिकों ने बंदी बना लिया था और कुछ वापस लौट गए थे, उन्होंने युद्ध के बारे में अपने सीनियर्स को बताया लेकिन किसी ने उनकी बातों को माना नहीं, क्योंकि बर्फ जम जाने की वजह से रेजांग ला में सबकुछ उसमें दफन हो गया था।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर
संपादकीय

वैश्विक शक्ति संतुलन

संपादक – राज कुमार

नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हाल ही में हुई घटनाओं ने भारतदृब्राज़ील संबंधों को एक नई दिशा दी है और वैश्विक शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण संकेत प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा की उपस्थिति में दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ तत्वों पर सहयोग संबंधी समझौते के साथ–साथ इस्पात आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये केवल औपचारिक कूटनीतिक दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता, रणनीतिक स्थिरता और दीर्घकालिक वैश्विक साझेदारी की स्पष्ट घोषणा हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिटिकल मिनरल्स समझौते को मजबूत और लचीली आपूर्ति शृंखला के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम बताया। आज के समय में जब वैश्विक आपूर्ति नेटवर्क भू–राजनीतिक तनाव, महामारी और व्यापारिक अस्थिरता से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे समझौते अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ब्राज़ील पहले से ही लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और अब दोनों देशों ने आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य दोहराया है। रक्षा क्षेत्र में बढ़ता सहयोग दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और रणनीतिक तालमेल को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति लूला ने भारत की तकनीकी क्षमताओं की खुलकर सराहना की। सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति को उन्होंने भविष्य की साझेदारी का आधार बताया। उनके साथ आए मंत्रियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की बड़ी टीम यह संकेत देती है कि यह संबंध केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक धरातल पर भी सशक्त हो रहा है। ब्राज़ील वैश्विक खनिज अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लौह अयस्क, मैंगनीज़, निकेल और नायोबियम जैसे खनिजों के उत्पादन में वह अग्रणी देशों में शामिल है। भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता निरंतर बढ़ रही है और बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ इसकी मांग भी बढ़ रही है। ऐसे समय में ब्राज़ील के साथ खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और उन्नत तकनीक में सहयोग भारत को कच्चे माल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। क्रिटिकल मिनरल्स समझौता केवल औद्योगिक आवश्यकता नहीं, बल्कि रणनीतिक अनिवार्यता भी है। विश्व में रेयर अर्थ तत्वों के उत्पादन और प्रसंस्करण पर लंबे समय से चीन का प्रभुत्व रहा है। भारत पिछले कुछ वर्षों से इस निर्भरता को कम करने की रणनीति पर कार्य कर रहा है। ब्राज़ील के साथ साझेदारी इस दिशा में ठोस आधार प्रदान करती है। रक्षा, ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, अंतरिक्ष और उच्च तकनीक उद्योगों के लिए इन खनिजों की स्थायी उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। यह साझेदारी केवल द्विपक्षीय हितों तक सीमित नहीं है। यह वैश्विक दक्षिण की सामूहिक आवाज को भी सशक्त करती है। जब दो बड़े लोकतंत्र खनिज, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते हैं, तो वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का संतुलन बदलता है। पश्चिमी शक्तियों और चीन के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा के दौर में यह समझौता एक संतुलित और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की संभावनाओं को मजबूत करता है। ऊर्जा क्षेत्र में जैव ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विमानन ईंधन पर सहयोग हरित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जलवायु अनुकूल कृषि और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना में साझा पहल विकासशील देशों के लिए उदाहरण बन सकती है। स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में भारत की सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं ब्राज़ील के लिए लाभकारी होंगी, वहीं भारतीय औषधि उद्योग को एक विशाल बाजार मिलेगा। भारत की विदेश नीति ने हाल के वर्षों में आत्मविश्वास और स्पष्टता दिखाई है। विविध साझेदारियों पर आधारित यह नीति पश्चिमी देशों के साथ गहरे संबंध, रूस के साथ रणनीतिक तालमेल और वैश्विक दक्षिण के साथ सघन सहयोग को संत. ुलित करती है। ब्राज़ील के साथ यह बढ़ती निकटता इसी व्यापक दृष्टि का हिस्सा है। अंततः यह समझौता एक रणनीतिक घोषणा है कि भारत अपने औद्योगिक और सामरिक भविष्य को किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं छोड़ेगा। यदि यह सहयोग योजनाओं से आगे बढ़कर ठोस परियोजनाओं में परिणत होता है, तो यह एशिया और लैटिन अमेरिका के बीच एक नए शक्ति सेतु का निर्माण करेगा और भारत को एक प्रभावशाली, आत्मनिर्भर और निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा।

तकनीक के जरिए मातृभाषाओं को बचाने की जरूरत

उमेश चतुर्वेदी

तकनीकी दौर में मातृभाषाएं सबसे ज्यादा संकट में हैं। इसकी वजह यह है कि मातृभाषाओं को बोलना भी तकनीक से प्रभावित हो रहा है और लेखन तो पूरी तरह उसी पर निर्भर हो गया है। तकनीक की खासियत कहें या कमी, वह बाजार के लिहाज से खुद को विकसित करती है और अपने उत्पादों के लिए इसी नजरिए से शोध करती है। चूंकि मातृभाषाओं में कई ऐसी हैं, जिन्हें बोलने या जिनका इस्तेमाल करने वालों की संख्या बेहद कम है, इसलिए उनसे कमाई की संभावना कम है। चूंकि तकनीकी विकास में काफी धन लगता है, और मातृभाषाओं के एक हिस्से से कमाई की गुंजाइश नहीं दिखती, इसलिए तकनीक उनके सहज इस्तेमाल में दिलचस्पी नहीं दिखाती। इसलिए मातृभाषाओं की बड़ी संख्या लुप्त होने के कगार पर हैं। भारत को ही देखिए। साल 1961 की जनगणना के आंकड़ों के लिहाज से भारत में 1652 भाषाएं थीं। लेकिन सिर्फ दस साल बाद यानी 1971 में यह संख्या घटकर महज 808 रह गई। ऐसा बदलाव तब हुआ, जब तकनीक का बोलबाला नहीं था। लेकिन अब बात उससे भी आगे बढ़ चुकी है। 2013 के भारतीय लोकभाषा सर्वेक्षण के अनुसार, विगत 50 वर्षों में 220 भाषाएँ जहां लुप्त हो गई हैं, वहीं 197 भाषाएँ खत्म होने की कगार पर हैं।

मातृभाषाओं के लुप्त होने की कई अन्य वजहें भी हैं। भाषाशास्त्रियों के मुताबिक, व्यक्तिवादी दर्शन, उपभोक्तावाद, सामा. जिक–सांस्कृतिक मूल्यों में आ रहे बदलाव, और शहरीकरण के साथ ही पारंपरिक मूल्यों के प्रति घटती निष्ठा और रोजगार के साधनों के रूप में भाषाओं की घटती संख्या भी मातृभाषाओं के खात्मे की वजह बना है। इसके बावजूद कुछ अपवादों को छोड़ दें तो मातृभाषाओं को लेकर कुछ इलाकों में सम्मोहन बरकरार है। शायद यही वजह है कि इस बार के अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के लिए यूनेस्को ने जो थीम रखा है, वह बेहद अहम जान पड़ता है। यह थीम है, 'भाषाओं का महत्वः रजत जयंती और सतत विकास'। इस थीम का ध्येय वाक्य 'अनेक भाषाएँ, एक भविष्य' है। पूर्वी बंगाल में 1952 में शहीद हुए भाषा आंदोलनकारियों की याद में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की शुरूआत की पिछले साल यानी 2025 में रजत जयंती थी। तब यूनेस्को ने इस दिवस को भाषाई विविधता, डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशी शिक्षा के माध्यम से सतत विकास पर जोर देने पर केंद्रित किया था।

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हर साल यूनेस्को किसी न किसी अहम विषय को ध्येय बनाता है और उस नजरिए से पूरे साल भाषाई विविधता को विकसित करने और उन्हें लागू करने पर जोर देता है। इस बार के ध्येय वाक्य से साफ है कि यूनेस्को चाहता है कि विश्व के सतत विकास में मातृभाषाओं की महत्ता को रेखांकित किया जाए। मातृभाषाएं एक तरह से भाषायी लो. कतंत्र को रचती हैं। इस लोकतंत्र को बचाए बिना विविधरंगी संसार को नहीं बचाया जा सकता। सोचिए, अगर उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद और तकनीकी वर्चस्व की वजह से एक रस और एक भाषायी संसार तैयार हो जाए तो दुनिया कितनी नीरस होगी, ज्ञान के तमाम स्रोत तब या तो सूख चुके होंगे या फिर भुला दिए गए होंगे। इसलिए मातृभाषाओं को बचाना और उन्हें सांस्कृतिक लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में जिंदा रखना जरूरी हो जाता है।

> तकनीकी युग में मातृभाषाएँ गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। बाजार आधारित तकनीकी विकास कम बोलने वालों की भाषाओं में निवेश नहीं करता, जिससे अनेक भाषाएँ लुप्त हो रही हैं। भारत में भी पिछले दशकों में सैकड़ों भाषाएँ समाप्त हो चुकी हैं या संकटग्रस्त हैं। यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के माध्यम से भाषायी विविधता, बहुभाषावाद और सतत विकास पर जोर दे रहा है।

यूनेस्को की ओर से घोषित 'भाषाओं का महत्व दृ रजत जयंती और सतत विकास' विषय, एक तरह से भाषायी विविधता, बहुभाषावाद और सतत विकास के बीच गहरे संबंधों को ही रेखांकित करता है। चूंकि यूनेस्को ने मातृभाषाओं को संरक्षित करने, भाषायी विविधता को जिंदा रखने और उन पर रश्क करने के साथ ही शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रयासरत है, इसलिए वह लगातार भाषाओं को बचाने का संदेश दे रहा है।

दुनिया में इन संदेशों को सुना और समझा भी जा रहा है। चूंकि भाषाएँ सिर्फ संवाद का साधन ही नहीं होतीं, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का अहम औजार भी हैं, लिहाजा प्राथमिक शिक्षा में उन पर जोर दिया जा रहा है। 2020 में आई भारत की नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषाओं में शिक्षा–विशेषकर प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। दुनियाभर के शिक्षाशास्त्री मानते हैं कि मातृभाषा आधारित शिक्षा समावेशी होती है और बच्चों की समझ को बेहतर बनाने में मददगार होती है। इतना ही नहीं, इसके चलते बच्चे की सीखने की प्रक्रिया भी तेज होती है। मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा के भी नतीजे बेहतर होते हैं। चूंकि सतत विकास में शिक्षा का स्थान अहम है और मातृभाषा आधारित शिक्षा बेहतरीन होती है, यही वजह है कि सतत विकास के लक्ष्यों को अब मातृभाषा के जरिए मिलने वाली शिक्षा में गंभीरता से खोजा जा रहा है। इसीलिए दुनिया एक बार फिर मातृभाषाओं के जरिए शिक्षा की ओर उन्मुख होती दिख रही है।

जैसे–जैसे अधिकाधिक भाषाएँ विलुप्त होती जा रही हैं, भाषायी विविधता खतरे में पड़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व की 40 प्रतिशत आबादी को उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल रहा है, जिन्हें वे बोलते या समझते हैं। मातृभाषाओं का संरक्षण इसलिए भी जरूरी है कि स्थानीय समाज उनके जरिए शिक्षा हासिल कर सकें।

मातृभाषा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सांस्कृतिक पहचान और बौद्धिक नींव की आधारशिला है। यह सोचने, समझने और संवाद करने का सबसे सहज माध्यम है, जो बच्चे को उसकी विरासत से जोड़ती है। मातृभाषा में शिक्षा से आत्मविश्वास बढ़ता है, संज्ञानात्मक कौशल विकसित होते हैं, और दूसरी भाषाएं सीखना आसान हो जाता है।

मातृभाषा में शिक्षा से बच्चे की अवधारणाओं को समझने की क्षमता तेज होती है और रचनात्मकता बढ़ती है। मातृभाषा संस्कृति, परंपराओं और इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का मुख्य माध्यम है। व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को मातृभाषा में सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सकता है, जिससे मानसिक स्पष्टता आती है।

शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार, जिन बच्चों की नींव मातृभाषा में मजबूत होती है, मातृभाषाओं से इतर भाषाओं में भी उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। मातृभाषाएं परिवार और समुदाय से एक मजबूत भावनात्मक संबंधों की गारंटी भी होती हैं।

दुनिया की हर मातृभाषा अपनी संस्कृति, परंपरा और इतिहास की संवाहक है। इसी वजह से दुनियाभर के मानवशास्त्री मानते हैं कि सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भाषायी विविधता का संरक्षण जरूरी है। इतना ही नहीं, मातृभाषाएँ आपसी समझ, सम्मान और सहयोग को भी बढ़ावा देती हैं, इस लिहाज से वे समावेशी समाज के निर्माण में भी सहायक मानी जाती हैं। मानवशास्त्रियों के अनुसार, स्थानीय भाषाएँ ज्ञान का खजाना हैं, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाना आवश्यक है। इसीलिए यूनेस्को का मानना है कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भाषायी विविधता और बहुभाषावाद का उपयोग सहयोगी हो सकता है।

इससे विश्व स्तर पर समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि मातृभाषाओं को तकनीक के लिहाज से विकसित किया जाए। यह कार्य सार्वजनिक संस्थान और सरकारें ही कर सकती हैं।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

भारत को वो असली धुरंधर, जिसने हिज्बुल मुजाहिदीन की जड़ें हिला दी

अभिनय आकाश

मार्च 2004 श्रीनगर की गहराइयों में बर्फीली पहाड़ी पर लकड़ी के घर में आतंकियों में अलग ही गहमागहमी मची हुई थी। हिजबुल मुजाहदीन का इफ्तिखार नाम का आतंकी रसोई में काहबा उबाल रहा था और दूसरे कमरे में अबू तुरारा और अबू सब्जार नाम के आतंकी आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। इसके बाद यह दोनों अपनी ।ज्ञ–47 को लोड कर लेते हैं और तभी इफ्तिखार ट्रे में काहबा के तीन कप पकड़े हुए कमरे में दाखिल होता है। इफ्तिखार को देखते ही काहबा के गिलास उठाने की जगह सब्ज़ार उस पर अपनी ।ज्ञ–47 तान देता है और गुस्से में कहता है इफ्तिखार मैं आखिरी बार पूछूंगा तुम कौन हो? इफ्तिखार अपने साथियों का ऐसा व्यवहार देख बड़ी सावधानी से ट्रे को नीचे रखता है और तुरंत हाथ ऊपर करके तुरारा की आंखों में देखते हुए कहता है भाईजान मैंने आपक. ो अपनी पूरी कहानी बताई थी फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा। एक काम करो आप मुझे अभी गोली मार दो, इतना सुन तुरारा और सब्जार एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तुरारा हां में सर हिलाता है जिसके बाद सब्जार अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। इसके बाद दोनों जमीन पर रख ही ट्रे से अपना–अपना काहबा का गिलास उठाते हैं और सामने रखी चारपाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इन दोनों की पीठ इफ्तिखार की तरफ होती है, वो तुरंत अपना बड़ा सा शॉल साइड करके अपनी कमर से पिस्तौल निकाल के लोड करता है। पिस्तौल लोड होने की आवाज सुनते ही तुरारा और सब्जार गर्दन घुमाते हैं। इतने में ही इफ्तिखार एक–एक करके दो गोली इनकी छाती से आर–पार कर देता है। यह इन आतंकियों के बीच कोई आपसी मनमुटाव नहीं था बल्कि यह इफ्तिखार भारत की वन पैरा एसएफ के जांबाज कमांडो मोहित शर्मा थे जो इन दोनों खूंखार आतंकियों को पिछले दो महीनों से मारने की ताक में थे।

यह वीनर्स नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है! और कीमत बहुत सस्ती है

जब से धुरंधर पिक्चर रिलीज हुई है। देश–दुनिया में इसी के चर्चा हैं। रणवीर सिंह के लुक्स, अक्षय खन्ना का डांस, अजित डोभाल जैसे गेटअप में आर माधवन। धुरंधर पिछले महीने 5 दिसंबर को रिलीज हुई। उसके बाद से एक बड़ा वर्ग इसकी बहुत तारीफ कर रहा है और अच्छा सिनेमा बता रहा है। फिल्म में भले ही रणवीर सिंह ने जसकीरत सिंह का फिक्शनल किरदार निभाया है। लेकिन जिसके बाद से ये चर्चा तेज है कि क्या वाकई में कोई ऐसा शेर था भी क्या? तो आज मातृभूमि में आपको बताएंगे कि फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार मेजर मोहित शर्मा से इन्सपायर है। मेजर मोहित शर्मा की कहानी फिल्म में दिखाए गए रणवीर सिंह के किरदार से कई गुणा खौफनाक और सच्ची थी। इसलिए रील की दुनिया से आगे बढ़कर आज आपके सामने रियल वाली कहानी सुनाते हैं। वो कहानी जिसे सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल जोर से धड़केगा और आंखें अपने आप नम हो जाएंगी। यह कहानी है हिंदुस्तान के उस शेर की जिसने मौत को सिर्फ गले नहीं लगाया बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर यह कहा कि आजा तू भी देख ले कि हिंदुस्तानी फौज की आखिरी सांस तक में कितनी ताकत छिपी होती है। यह कहानी है मेजर मोहित शर्मा की जो कश्मीर गया आतंकी लोगों के साथ रहा। उनके बिस्तर पर सोया। खतरनाक हिजबुल कमांडरों के साथ कहवा पिया और उनकी आंखों में झूठ का सुरमा लगाया। हफ्तों तक भरोसा जीता और फिर एक पल में हिंदुस्तान के लिए उनकी छाती में गोली दाग कर उन्हें जहन्नुम का टिकट दे दिया।

रोहतक की ठंडी सुबह थी। एक छोटा बच्चा स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। बेटा क्या बनोगे बड़े होकर? उसका नाम मोहित शर्मा था। घर में चिंटू एनडीए में माई और भारत के लिए शैडो वॉरियर। सपनों का यूनिफार्म इंजीनियरिंग की किताबें बंद हो चुकी थी। उसे अपना जीवन, गणित और मशीनों नहीं, धरती और देश को देना था। एनडीए के गेट पर कदम रखते ही उसने महसूस किया यह मात्र प्रशिक्षण नहीं यह रूपांतरण है। 1999 में कमीशन मिला। फिर उसने चुना वह रास्ता जहां से लौट कर आने की कोई गारंटी नहीं होती। वेट पारा स्पेशल फोर्सेस जहां हर पल मौत के साथ दोस्ती करनी पड़ती है। उसने मौत से दोस्ती कर ली क्योंकि उसे जिंदगी से प्यार था और देश से भी। 2004 का साल कश्मीर दहशत से भरा हुआ था। दुश्मनों में घुसने का प्लान बना। एक कमांडो ने अपनी पहचान उतार को बदला और नया नाम लिया इफ्तिखार भट्ट। उसने कहा मेरा भाई सेना ने मार दिया। मैं बदला लेना चाहता हूं। आतंकियों ने उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें परखी। उसकी नब्ज़ जांची। उसे शक हुआ पिस्तौल उसके सिर पर लगा दी गई। कमरे में सन्नाटा था। धड़कनें जैसे रोक दी गई। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर भरोसा नहीं तो गोली मार दो। उसी क्षण उसनेबिजली की रफ्तार से 9 एमएम निकालकर दो बड़े आतंकियों को वहीं खत्म कर दिया और पल भर में वह दुश्मनों का साझेदार नहीं उनका अंत बन चुका था। इस मिशन की रिपोर्ट आज भी पूरी दुनिया नहीं जानती।

अक्टूबर 2008 फिर कश्मीर का बुलावा आया। मार्च 2009 में कश्मीर में बर्फ पिघल रही थी। 20 मार्च की दोपहर कुपवाड़ा बेस खबर आई कि हफ्रूदा जंगल में आतंकी घुसे हैं। मेजर मोहित को 25 कमांडोस के साथ आर्डर मिला। रात 2रू30 बजे निकले। सुबह 4रू00 बजे जगह पर थे। चारों तरफ घना जंगल कोई सुराग नहीं। सुबह 8रू00 बजे तीन टीमों बंटे। मोहित खुद एक टीम के साथ। बर्फ में पैरों के निशान मिले। एक के ऊपर मतलब आतंकी हाईली ट्रेंड थे। पीछा किया। तभी दूसरी टीम का मैसेज आया दो आतंकी दिखे हैं। अगले ही पल जंगल में गोलियों की बौछार होने लगी। रेडियो पर आर्डर आया कि राकेश चोटी पर चढ़ो। ऊपर से बरसाओ। हवलदार राकेश चढ़े। गोली जांघ पर लगी। लेकिन फिर भी लड़खड़ाते हुए एक हाथ से फायरिंग जारी रखी। इसके बाद मोहित ने जवानों को पीछे भेजा और खुद कवर फायर किया। उनके साथी कहने लगे कि सर मोहित बोले नहीं आप जाओ मैं आता हूं। बात खत्म होते–होते गोली बाहों पर लगी। खून बहा लेकिन फिर भी फायरिंग जारी थी। ज्यादातर जवान कवर में पहुंचे तो फिर एक और आर्डर आया। तब तक गोली फिर लगी थी कोहनी पर, जिसे देख आतंकी खुश थे। लेकिन इसके बाद मोहित ने खुद एमजेल उठाया और एक दो तीन नहीं बल्कि छह ग्रेनेड से चार आतंकवादियों को ढेर कर दिया। फायरिंग रुकी मोहित कवर की तरफ दौड़े। तभी एक सन्नाटा चीरती गोली साइड से आ गई। गोली आरपार गई। मोहित लड़खड़ाए गिर पड़े। हालांकि मोहित ने अपने साथियों से कहा कि मैं ठीक हूं। आज इनमें से एक भी आतंकवादी बचकर जाना नहीं चाहिए। खून से लथपथ पेड़ से टेक लगाकर खड़े रहे। शाम 4रू00 बजे तक निकाले गए। काफी खून बह चुका था। श्रीनगर बेस हॉस्पिटल रहे। पूरी रात ऑपरेशन चला लेकिन सुबह 31 साल की उम्र में वो शेर अमर हो गया था। पांच दिन में जंगल साफ हो गया था। सभी आतंकवादी मार दिए गए थे। बाद में पता चला कि एक के पास हाई जूम स्नाइपर थी। इसलिए कवर से हटते ही गोली लग रही थी। मेजर मोहित समेत सात जवान शहीद हुए थे।

मेजर मोहित की वीरता के लिए देश का सबसे बड़ा शांति काल अवार्ड अशोक चक्र उन्हें मरणोपरांत मिला। मेजर मोहित की पत्नी, लेफ्टिनेंट कर्नल (तब मेजर) रिशिमा शर्मा, भी भारतीय सेना में एक ऑफिसर हैं। वह 2001 में आर्मी सर्विस कोर में सेना में शामिल हुईं, जो उनके पिता का भी कोर है। उनके भाई भारतीय सेना में कर्नल हैं, जो आर्टिलरी रेजिमेंट में सेवारत हैं। यह बताना जरूरी है कि रिशिमा सरीन पहली महिला ऑफिसर थीं जो 2023 में अग्निवीर रिक्रूटर बनीं। गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़कें स्टेडियम उनके नाम है। मगर सबसे बड़ा स्मारक तो हर हिंदुस्तानी का दिल है जहां पर आज भी वो जिंदा है। वो गरजते हैं, लड़ते हैं। और जब कोई पूछता है कि सच्चा हीरो कौन है? तो एक नाम निकलता है मेजर मोहित शर्मा। वो नाम जिसने साबित किया कि एक फौजी की सांस में पूरा हिंदुस्तान बसता है।

मेजर मोहित शर्मा भारतीय सेना की 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस के जांबाज कमांडो थे, जिन्होंने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अद्भुत साहस दिखाया। वर्ष 2004 में उन्होंने 'इफ्तिखार भट्ट' नाम से हिजबुल मुजाहिदीन में घुसपैठ की। कई हफ्तों तक आतंकियों के बीच रहकर उनका विश्वास जीता और सही मौके पर दो खूंखार आतंकियों को मार गिराया। यह मिशन भारतीय सेना के सबसे साहसी ऑपरेशनों में गिना जाता है। रोहतक में जन्मे मोहित ने इंजीनियरिंग छोड़कर एनडीए का रास्ता चुना और 1999 में कमीशन प्राप्त किया। उन्होंने स्वेच्छा से पैरा एसएफ जॉइन की, जहां हर दिन जान का जोखिम होता है। मार्च 2009 में कुपवाड़ा के हफरूदा जंगल में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उन्होंने घायल होने के बावजूद अपने साथियों को सुरक्षित निकलने का आदेश दिया और खुद मोर्चा संभाले रखा। कई गोलियां लगने के बाद भी उन्होंने चार आतंकियों को ढेर किया। गंभीर रूप से घायल होने पर भी उनका अंतिम संदेश थाकृ "एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए।" 31 वर्ष की आयु में वे शहीद हो गए। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया।

भारतीय सेना के वीर जवानों की शौर्य गाथा

देश के वीर जवानों से जुड़ी कई कहानियाँ भी हैं जो न सिर्फ़ आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी, बल्कि उनकी कुर्बानियाँ आपकी आँखों को नम कर देंगी। वे फौलादी योद्धा हैं, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं। वे कड़ाके की ठंड और चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना हमेशा बहादुर, सजग और हमारे प्रति समर्पित रहते हैं। वे सभी नायक हैं, हर एक। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कहानियाँ किंवदंतियों का विषय बन गई हैं।

अभिनय आकाश

जब भी शांति की बात होती है, तो भारत का ज़िक्र सबसे पहले आता है। यही काम भारतीय सेना भी कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की शांति में भारतीय सेना का सबसे बड़ा योगदान रहा है। भारत इस बात के लिए भी जाना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के तहत स्थापित पहली महिला पुलिस अधिकारी भारत की ही थीं। क्या यह बहुत बड़ी बात नहीं है? अगर हम सेना की बात करें, तो सेना न सिर्फ़ देश की सुरक्षा में योगदान दे रही है, बल्कि देश के निर्माण और बुनियादी ढाँचे में भी उसका बड़ा योगदान है। देश के वीर जवानों से जुड़ी कई कहानियाँ भी हैं जो न सिर्फ़ आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी, बल्कि उनकी कुर्बानियाँ आपकी आँखों को नम कर देंगी। वे फौलादी योद्धा हैं, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं। वे कड़ाके की ठंड और चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना हमेशा बहादुर, सजग और हमारे प्रति समर्पित रहते हैं। वे सभी नायक हैं, हर एक। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कहानियाँ किंवदंतियों का विषय बन गई हैं।

1. कैप्टन विक्रम बत्रा

हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्मे, 13 जेएंडके राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल युद्ध का नायक माना जाता है। उन्होंने कश्मीर में सबसे कठिन युद्ध अभियानों में से एक का नेतृत्व किया और उन्हें शेरशाह भी कहा गया। 17,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित चोटी 5140 पर पुनः कब्ज़ा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस अभियान के दौरान, बत्रा गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने करीबी मुकाबले में तीन दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। चोटी 5140 पर कब्ज़ा करने के बाद, वे 7 जुलाई, 1999 को चोटी 4875 पर पुनः कब्ज़ा करने के लिए एक और कठिन अभियान पर निकल पड़े। बत्रा ने जाने से पहले अपने पिता को फ़ोन किया और उन्हें इस महत्वपूर्ण अभियान के बारे में बताया। उन्हें शायद ही पता था कि यह घर पर उनका आखिरी फ़ोन होगा। यह भारतीय सेना द्वारा किए गए सबसे कठिन अभियानों में से एक था क्योंकि पाकिस्तानी सेनाएँ चोटी से 16,000 फीट ऊपर बैठी थीं और चढ़ाई का ढलान 80 डिग्री था। ऊपर जाते समय, बत्रा का एक साथी अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया। बत्रा उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। जब एक सूबेदार ने उस अधिकारी को बचाने में उनकी मदद करने की कोशिश की, तो बत्रा ने उसे यह कहते हुए किनारे कर दिया, तुम्हारे बच्चे हैं, किनारे हट जाओ। उन्होंने अपने साथी सैनिक को तो बचा लिया, लेकिन दुश्मन के ठिकानों को साफ़ करते समय शहीद हो गए। बत्रा के अंतिम शब्द थे, जय माता दी।

2. मेजर जनरल इयान कार्डोज़ो

मेजर जनरल इयान कार्डोज़ो, जिनके नाम अनगि. नत उपलब्धियाँ हैं, 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में उनके अदम्य साहस के लिए हमेशा याद किए जाएँगे। उस समय वे 5 गोरखा राइफल्स में एक युवा मेजर थे। युद्ध के दौरान, वे एक बारूदी सुरंग पर पैर रखकर गंभीर रूप से घायल हो गए। जब डॉक्टर भी उनका पैर नहीं काट पाए, तो कार्डोज़ो ने एक खुखरी (गोरखा चाकू) मँगवाई और अपना पैर यह कहते हुए काट दिया, अब जाओ और इसे दफना दो। इस घटना ने कार्डोज़ो को देश सेवा के लिए आगे बढ़ने से नहीं रोका। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के बल पर, उन्होंने एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन जारी रखा और भारतीय सेना में एक पैदल सेना बटालियन और एक ब्रिगेड की कमान संभालने वाले पहले विकलांग अधिकारी बने। शारीरिक रूप से अन्य अधिकारियों के बराबर

न होने के बावजूद, उन्होंने सेना में अपने कार्यकाल के दौरान कई फिटनेस परीक्षणों में कई श्दो पैरों वालेश सैनिकों को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया।

3. ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान

उत्तर प्रदेश के बीबीपुर में जन्मे, यह इस्पात पुरुष 1934 में भारतीय सेना में शामिल हुए। 1947/48 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के दौरान, ब्रिगेडियर उस्मान ने जम्मू और कश्मीर के दो अत्यधिक रणनीतिक स्थानों, नौशेरा और झांगर पर एक भीषण हमले को विफल कर दिया, और उनके साथी सैनिकों ने उन्हें श्नौशेरा का शेरश नाम दिया। विभाजन के समय, उन्हें पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया। उन्होंने पाकिस्तान की बलूच रेजिमेंट छोड़ दी और भारत में डोगरा रेजिमेंट में शामिल हो गए। नौशेरा की लड़ाई के बाद, जहाँ पाकिस्तानियों को उनके हाथों भारी क्षति हुई, उसी देश ने, जिसने उन्हें सेना प्रमुख बनने के लिए आमंत्रित किया था, अब आगे बढ़कर उन पर 50,000 रुपये का इनाम रख दिया। ब्रिगेडियर उस्मान न केवल एक वीर सैनिक थे, बल्कि एक दयालु व्यक्ति भी थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा और उनके पालन–पोषण के लिए दान कर देते थे। भारतीय सेना के इस प्रेरक और अनुकरणीय अधिकारी का 3 जुलाई, 1948 को झांगर की रक्षा करते हुए निधन हो गया।

4. सूबेदार योगेन्द्र सिंह यादव

इस वीर सैनिक को परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त है। उन्हें यह सम्मान 19 वर्ष की आयु में 4 जुलाई, 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान उनके कार्यों के लिए प्रदान किया गया था। 1980 में उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद अहीर गाँव में जन्मे यादव ने 1999 के युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने टाइगर हिल पर तीन रणनीतिक बंकरों पर कब्ज़ा करने के कार्य के लिए स्वेच्छा से आगे आए, जो एक ऊर्ध्वाधर, बर्फ से ढकी, 16,500 फीट ऊँची चट्टान के शीर्ष पर स्थित थे। वह रस्सी के सहारे ऊँची चट्टान पर चढ़ रहे थे, तभी दुश्मन के बंकर से रॉकेट दागे जाने लगे। यादव की कमर और कंधे में तीन गोलियां लगीं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, यादव चढ़ते रहे और चट्टान की चोटी तक पहुँचने के लिए शेष 60 फीट की चढ़ाई पूरी की। अत्यधिक दर्द में होने के बावजूद, यादव रेंगते हुए पहले दुश्मन बंकर तक पहुँचे और एक ग्रेनेड फेंका, जिससे चार पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और दुश्मन की गोलाबा. री रुक गई। इससे शेष भारतीय पलटन को चट्टान पर चढ़ने का अवसर मिला। हालाँकि, बात यहीं खत्म नहीं हुई। यादव ने लड़ाई जारी रखी और दो साथी सैनिकों की मदद से दूसरे बंकर को भी तबाह कर दिया। दरअसल, उन्होंने दुश्मन के साथ आमने–सामने की लड़ाई भी लड़ी और चार और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।

5. राइफलमैन जसवंत सिंह रावत

इस वीर पुरुष की कहानी कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। 1962 के भारत–चीन युद्ध के नायक, चौथी गढ़वाल राइफल्स इन्फैंट्री रेजिमेंट के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, भारतीय सेना के इतिहास में एकमात्र ऐसे सैनिक हैं जो अपनी मृत्यु के बाद भी उच्च पदों पर पहुँचे। उनकी मृत्यु के 40 साल बाद उन्हें मेजर जनरल के पद पर श्पदोन्नतश किया गया था, और माना जाता है कि आज भी वे चीन से लगती भारत की पूर्वी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों की श्कमानश संभालते हैं। 1962 के युद्ध के दौरान, नूरानांग की लड़ाई में चीनियों के हाथों भारी क्षति के कारण सैनिकों को जल्द से जल्द अपनी चौकियाँ खाली करने का आदेश दिया गया था। लेकिन जसवंत ने अपनी जगह नहीं छोड़ी और अन्य सैनिकों के चले जाने के बाद भी लड़ते रहे। रावत की मदद सेला और नूरा नाम की दो मोनपा आदिवासी लड़कियों ने की। तीनों ने अलग–अलग जगहों पर हथियार तैनात किए और गोलीबारी की तीव्रता बनाए रखी ताकि चीनियों को लगे कि उनका सामना एक विशाल सेना से हो रहा है। रावत तीन दिनों तक उन्हें चकमा देने में कामयाब रहे। लेकिन चीनियों को इस योजना के बारे में एक ऐसे व्यक्ति के ज़रिए पता चल गया जो रावत और दोनों लड़कियों को राशन पहुँचाता था। रावत ने चीनी सेना द्वारा पकड़े जाने के बजाय खुद को गोली मारने का फैसला किया। यह जानकर कि वे इतने समय से एक ही सैनिक से लड़ रहे थे, चीनी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने रावत का सिर काटकर चीन वापस ले गए।

6. सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल

पुणे में जन्मे, 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट के द्वितीय लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल भी एक ऐसे ही वीर थे, जिनकी 21 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई। 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के दौरान बसंतर की लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, जहाँ उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। खेत्रपाल ने दिसंबर 1971 में शकरगढ़ सेक्टर के जरपाल में, जब पाकिस्तानी बख्तरबंद गाड़ियों ने, जो ताकत में उनसे बेहतर थीं, जवाबी हमला किया, तो उन्होंने अदम्य साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया। हालाँकि खेत्रपाल एक अलग स्क्वाड्रन में थे, फिर भी वे मदद के लिए दौड़ पड़े, दुश्मन की ओर बढ़े, अपने टैंकों से रक्षा पंक्ति को भेद दिया और पाकिस्तानी पैदल सेना और हथियारों पर कब्ज़ा कर लिया। अपने सैनिकों के कमांडर के शहीद होने के बाद भी, खेत्रपाल ने दुश्मन पर तब तक भीषण हमला जारी रखा जब तक कि उनके टैंक पीछे हटने नहीं लगे। खेत्रपाल ने पीछे हटते हुए एक टैंक को भी नष्ट कर दिया।

लेकिन दुश्मन ने अपने कवच में सुधार किया और दूसरे हमले की तैयारी की। इस बार उन्होंने खेत्रपाल के कब्जे वाले क्षेत्र को निशाना बनाया। हमला ज़ोरदार और तेज़ था। खेत्रपाल घायल हो गए, लेकिन दुश्मन के 10 टैंकों को नष्ट करने में कामयाब रहे। उन्हें अपना टैंक छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने इसे छोड़ दिया, तो दुश्मन अंदर घुस जाएगा। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दुश्मन के एक और टैंक को नष्ट कर दिया। लेकिन तभी उनके अपने टैंक पर एक और हमला हुआ, जिसके परिणामस्वरूप इस साहसी अधिकारी की मृत्यु हो गई।

7. मेजर सोमनाथ शर्मा

चौथी कुमाऊँ रेजिमेंट के इस बहादुर सिपाही ने 24 साल की छोटी सी उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। हॉकी के एक खेल में लगी चोट के कारण उनके हाथ पर पहले से ही प्लास्टर चढ़ा हुआ था, फिर भी शर्मा ने 30 अक्टूबर, 1947 को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए जब अपनी कंपनी को हवाई मार्ग से श्रीनगर लाया गया, तो युद्ध में उनके साथ रहने की ज़िद की। 3 नवंबर को जब शर्मा की कंपनी बड़गाम गाँव में गश्त पर थी, तभी गुलमर्ग की ओर से 700 हमलावरों का एक कबायली लश्कर उन पर टूट पड़ा। कंपनी को जल्द ही तीन तरफ से घेर लिया गया और उसके बाद हुई भारी मोर्टार बमबारी में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह महसूस करते हुए कि अगर वे इस समय युद्ध छोड़ देते हैं तो श्रीनगर और हवाई अड्डा असुरक्षित हो जाएगा, शर्मा एक चौकी से दूसरी चौकी तक दौड़ते रहे और अपने जवानों को एक ऐसे दुश्मन का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे जिसकी संख्या उनसे सात गुना ज़्यादा थी। जब भारी क्षति ने उनकी मारक क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया, तो बाएँ हाथ पर प्लास्टर लगे शर्मा ने लाइट मशीन गन चलाने वालों के लिए मैगज़ीन भरने का काम शुरू कर दिया। जब वह लड़ाई में व्यस्त थे, तभी एक मोर्टार का गोला उनके पास रखे गोला–बारूद पर फट गया, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई।

8. नायक जदु नाथ सिंह

चौथे परमवीर चक्र विजेता नायक जदु नाथ सिंह ने 1947/48 के भारत–पाक युद्ध में जम्मू और कश्मीर में लड़ाई लड़ी थी।

उनकी सूझबूझ और बहादुरी ने उनकी चौकी को एक बार नहीं, बल्कि तीन बार दुश्मन से बचाया। 6 फ़रवरी, 1948 के उस महत्वपूर्ण दिन, सिंह तैनधार में एक अग्रिम चौकी की कमान संभाल रहे थे। उस चौकी पर नौ सैनिक तैनात थे। पाकिस्तानियों ने इस चौकी पर कब्ज़ा करने के लिए लगातार हमले शुरू कर दिए। ऐसे समय में, सिंह ने शानदार नेतृत्व का परिचय दिया और अपनी छोटी सी सेना का इस तरह इस्तेमाल किया कि दुश्मन पूरी तरह से घबराकर पीछे हट गया। चार घायल सैनिकों के साथ, उन्होंने अपनी सेना को एक और हमले का सामना करने के लिए पुनर्गठित किया। संख्या में कम होने के बावजूद, उन्होंने हार नहीं मानी। जब उनके सभी सैनिक, जिनमें वे स्वयं भी शामिल थे, घायल हो गए, तो उन्होंने घायल गनर से ब्रेन गन ले ली और लड़ाई जारी रखी। दुश्मन अब चौकी की दीवारों पर थे, लेकिन सिंह की गोलाबारी इतनी विनाशकारी थी कि चौकी दूसरी बार भी बच गई। अब तक उनकी चौकी का हर व्यक्ति मर चुका था। पाकिस्तानी फिर से तीसरे हमले के लिए आए।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

राँजड़ी, जम्मू में सत्संगरू सुमिरन से ही मिलेगा मन पर नियंत्रण - साहिब बंदगी के सद्गुरू साहिब जी

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू, राँजड़ीरू साहिब बंदगी के सद्गुरु साहिब जी ने राँजड़ी, जम्मू में आयोजित आध्यात्मिक सत्संग में प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए कहा कि जीवन में नाम सुमि. रन सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुमि. रन ही आत्मा को पार लगाता है और मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल मार्ग है।

सद्गुरु साहिब जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कोई समझदार व्यक्ति रुपये को फाड़कर नहीं फेंकता क्योंकि वह उसके महत्व को जानता है, उसी प्रकार सुमिरन के महत्व को समझना आवश्यक है। जप, तप और साधनाकृंसस सुमिरन में ही समा. हित हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुमिरन के समान कुछ भी नहीं है।

उन्होंने बताया कि सुमिरन का अर्थ केवल प्रभु का नाम दोहराना नहीं, बल्कि एकाग्रता प्राप्त करना है। "सुमिरन से मन एकाग्र होता है। मन एक सेकेंड भी शांत नहीं रहता। वह हमेशा सोचता, योजना बनाता या कोई क्रिया करता रहता है," उन्होंने कहा। सद्गुरु जी ने समझाया कि बैठना, लेटना, सोचनाकृसब क्रिया के रूप हैं। यहां तक कि सांस लेना भी एक क्रिया है। मन को कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, लेकिन क्रिया को रोकना अत्यंत कठिन है। यही अहंकार का रूप है। क्रिया से रहित अवस्था को ही शून्य कहा गया है। उन्होंने कहा कि आत्मा प्राणों में बंधी है और प्राणों के शरीर से अलग होने को ही मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के बाद भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि आत्मा अमर है। अंत में सद्गुरु साहिब जी ने कहा कि सच्ची एकाग्रता पाने के लिए सांसों के साथ सुमिरन करना आवश्यक है। स्वांस के साथ किया गया सुमिरन मन को शांत और एकाग्र बनाता है तथा आत्मिक शांति प्रदान करता है।

हड़ताल श्रमिक अधिकारों को कमजोर करती है

एस. पी. तिवारी

चार नयी श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन, भारत की विशाल श्रम शक्ति, विशेष रूप से अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए जीवन यापन में आसानी में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सुधारों का उद्देश्य, बिना जटिल उद्योग वर्गीकरण की बाधाओं के, सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देना है। प्रत्येक श्रमिक के लिए अनिवार्य पहचान पत्र की शुरुआत करते हुए, ये संहिताएं उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभों तक सीधी पहुंच की सुविधा के साथ सशक्त बनाने का प्रयास करती हैं। नियमित और अनिवार्य स्वास्थ्य जांच, श्रमिकों की भलाई में मदद करेंगी, जिससे वे स्वस्थ और अधिक उत्पादक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसके अलावा, समयबद्ध शिकायत निवारण व्यवस्था, पीड़ित श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले मानसिक तनाव और अनिश्चितता को कम करने में सहायता करेगी। समग्र रूप से, ये उपाय भारतीय श्रमिकों के लिए गरिमा, सुरक्षा और समावेशी विकास पर केंद्रित एक प्रगतिशील रूपरेखा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हालाँकि, इन सकारात्मक प्रावधानों के बावजूद, राजनीतिक रूप से प्रेरित केंद्रीय श्रमिक संघों (ट्रेड यूनियन) का एक हिस्सा अक्सर हड़ताल के प्रतिक. ूल प्रभाव पर पूरी तरह विचार किए बिना, हड़ताल पर उतर आता है। ऐसी हड़तालों से विशेष रूप से असंगठित अर्थव्यवस्था के लगभग 38 करोड़ श्रमिकों के पारिश्रमिक को भारी नुकसान होता है, जो अपनी जीविका के लिए दैनिक आय पर निर्भर होते हैं। उनके मुद्दों को हल करने के बजाय, बार–बार होने वाली हड़तालें रचनात्मक और कठोर सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को कमजोर करती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के लिए न्यायसंगत और संतुलित परिणाम हासिल करने की संभावना कम हो जाती है।

समय के साथ, बार–बार हड़ताल बुलाने का प्रयास न केवल अप्रभावी साबित हुआ है बल्कि इसके परिणाम प्रतिकूल भी रहे हैं। बार–बार होने वाली हड़तालों से श्रमिकों में व्यापक थकान दिखाई पड़ता है, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिक ऐसे आह्वान को या तो नजरअंदाज करते हैं या उनमें शामिल नहीं होते हैं। कुछ मामलों में, श्रमिकों के एक छोटे हिस्से को उनकी इच्छा के विपरीत हड़तालों में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे इन आंदोलनों की नैतिक वैधता व सामूहिक ताकत और कमजोर हो जाती है। अंततः, यह प्रवृत्ति श्रमिक कल्याण उपायों के समग्र प्रभाव को कम करती है और श्रमिकों के बीच एकजुटता को कमज़ोर करती है।

हड़तालों के व्यापक परिणाम केवल कार्यस्थल तक सीमित नहीं रहते। औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होता है, दैनिक यात्रियों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ता है, और सड़क किनारे के विक्रेताओं, घरेलू श्रमिकों और छोटे सेवा प्रदाताओं की आजीविका बाधित हो जाती है। इन श्रमिकों के लिए, केवल एक दिन की आय का नुकसान भी आजीविका संकट पैदा कर सकता है, उन्हें अपनी सीमित बचत को खत्म करने तथा गंभीर आर्थिक असुरक्षा में जाने के लिए मजबूर कर सकता है।

भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में, श्रमिक संघों (ट्रेड यूनियन) को संवाद, आपसी–बातचीत और नियोक्ताओं तथा सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्थायी सौदेबाजी और सहयोगात्मक समस्या समाधान पर आधारित एक मॉडल उत्पादन, रोजगार, और समग्र आर्थिक वृद्धि को बाधित किए बिना श्रमिकों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। वर्तमान संदर्भ में, भारतीय केंद्रीय श्रमिक संघों को, जो धीरे–धीरे अपना प्रभाव खो रहे हैं, आत्मविश्लेषण करने और अन्यत्र अपनाई जाने वाली अधिक प्रभावी और दूरदर्शी तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है।

भारतीय श्रमिक को एक समग्र दृष्टिकोण के साथ संगठित किया जाना चाहिए, जो जीवन यापन में आसानी, सामाजिक सुरक्षा और सकारात्मक सहभागिता पर जोर देता हो। विवादों का समाधान टकराव के बजाय संवाद के माध्यम से करना यह सुनिश्चित करेगा कि परिचालन प्रक्रिया बाधित न हो और राष्ट्रीय विकास की गति सुचारू रूप से जारी रहे। केवल ऐसे संतुलित और व्यावहारिक रणनीतियों के जरिये ही श्रमिकों के अधिकारों को वास्तविक रूप में मजबूत और दीर्घावधि में सुरक्षित किया जा सकता है।

(लेखक ट्रेड यूनियन को–ऑर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी) के राष्ट्रीय महासचिव हैं)

पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से न्यायिक अधिकारियों को जोड़ने के सुप्रीम फैसले के राष्ट्रीय मायने

कमलेश पांडे

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (ैप्) मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है, जिसमें लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी वाली एंट्रीज (जैसे माता–पिता का नाम मेल न खाना या आयु अंतर असंगत होना आदि की गहन जांच होती है। इसी को लेकर राज्य सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग के बीच उभरे विवाद को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 19–20 फरवरी 2026 को कलकत्ता हाईकोर्ट को वर्तमान और पूर्व न्यायिक अधिकारियों (जिला जज रैंक के) को तैनात करने का निर्देश दिया। ऐसा इसलिए कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग (म्ब्) के बीच विश्वास की कमी और सहयोग न होने से प्रक्रिया अटक गई थी।

लिहाजा इस अप्रत्याशित फैसले के राष्ट्रीय मायने अहम व दूरगामी साबित होंगे, क्योंकि यह फैसला असाधारण परिस्थितियों में न्यायपालिका को निर्वाचन प्रक्रिया में सीधे शामिल करने का बेजोड़ उदाहरण है, जो राज्य–केंद्र संबंधों में तनाव को उजागर करता है। देखा जाए तो यह अन्य राज्यों (जैसे केरल, तमिलनाडु) में ैप् विस्तार पर भी प्रभाव डाल सकता है, जहां समान विवाद हो सकते हैं। खास बात यह कि कोर्ट ने 'ट्रस्ट डेफिसिट' और 'ब्लेम गेम' की आलोचना की, जो संवैधानिक संस्थाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता पर जोर देता है।

हालांकि इसको लेकर कुछ सार्वजनिक प्रभाव और चिंताएं दोनों हैं। यह ठीक है कि न्यायिक अधिकारियों की तैनाती से दावों–आपत्तियों का निपटारा तेज होगा, और उनकी निर्णय अदालती आदेश माने जाएंगे। हालांकि, इससे नियमित अदालती कार्य प्रभावित हो सकता है, जिसके लिए हाईकोर्ट को वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा गया है। यह बात अलग है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्वाचन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप को मजबूत बनाता है, लेकिन राज्य सरकारों पर सहयोग न करने का दबाव बढ़ाता है। यूँ तो इस फैसले से अन्य राज्यों पर सीधा कानूनी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे पश्चिम बंगाल की "असाधारण परिस्थितियों" (ट्रस्ट डेफिसिट और ब्लेम गेम) तक सीमित रखा। लेकिन जहां तक अन्य राज्यों में ैप् स्थिति का सवाल है तो केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां ैप् पहले ही चल रहा था या विवादास्पद रहा, वहां बंगाल जैसी न्यायिक हस्तक्षेप की कोई तत्काल मांग नहीं दिख रही। वहीं 12 राज्यों (यूपी, बंगाल सहित) में ैप् प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ चुकी, फॉर्म वितरण 95 प्रतिषत पूरा हो चुका है।

साप्ताहिक राशिफल

मेष

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी कभी गम लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपक.ो निजी जीवन से लेकर करियर–कारोबार तक में उतार–चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहने वाली है। इस दौरान व्यक्तिगत और पेशेवेर रूप से खुद को मजबूत पाएंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। युवाओं का अधिकांश समय मौज–मस्ती करते हुए बीतेगा। घर–परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सप्ताह के मध्य में आपको करियर–कारोबार में कुछ अप्रत्याशित बदलाव को झेलना पड़ सकता है।

इस दौरान नौकरीपेशा लोगों के सिर पर अचानक से अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है। जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता रहेगी।

वृषभ

वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। वृष राशि के जो जातक किसी कार्य विशेष के लिए बीते कुछ समय से लगातार प्रयासरत हैं, उन्हें इस सप्ताह भी उससे जुड़ी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले उनका पूर्वार्ध थोड़ा राहत भरा रहने वाला है।

ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने करियर–कारोबार और जीवन से जुड़े अहम कार्यों को इसी दौरान करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष से मेल–मुलाकात होगी। जिसकी मदद से अटके कार्यों में धीमी गति से ही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में न सिर्फ कार्यक्षेत्र से जुड़ी बल्कि घर–परिवार से संबंधित समस्याएं भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति अथवा किसी जमीन–जायदाद को लेकर विवाद हो सकता है। अचानक से जीवन में तमाम तरह की समस्याएं सामने आने से आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। हालांकि सुखद पहलू यह है कि इस दौरान आपके संगी–साथी आपकी ढाल बनेंगे और आपके साथ साए की तरह बने रहेंगे।

मिथुन

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप किसी कार्य विशेष के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो उम्मीद का दामन बिल्कुल न छोड़ें क्योंकि इस सप्ताह उसमें आ रही बाधाएं स्वतरू दूर होती हुई नजर आएंगी। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय नौकरीपेशा लोगों के लिए अनुकूल रहने वाला है।

इस दौरान आपके शुभचिंतक आपको नेक सलाह देते हुए नजर आएंगे, जिस पर अमल करके आप अपनी चीजों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में किसी तीर्थ स्थान पर जाने का अचानक प्रोग्राम बन सकता है। इस पूरे सप्ताह घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक–कार्यों में खूब रमेगा। किसी धार्मिक–आध्यात्मिक व्यक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुक.ाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप आप समझदारी के साथ अपने पैसे का सही जगह निवेश करते हैं तो आपको उससे भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आएगा।

कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक.ों को किसी भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। रिश्ते–नाते में मिठास बनी रहे और किसी प्रकार की गलतफहमी न पैदा हो इसके लिए स्वजनों के साथ संवाद बनाए रखें।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर–कारोबार के सिलसिले में बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसा करते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर को मिलाकर चलें। यदि कार्यक्षेत्र पर हालात आपके अनुकूल नहीं हैं तो आप उससे बजाय भागने के उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। भूलकर भी आवेश में आकर नौकरी में बदलाव जैसा फैसला लेने से बचें। सप्ताह के मध्य में घरेलू समस्याओं के चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपको आपके विरोधी आप पर हावी होने तथा आपके बनते काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।

सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक.ों को अपनी ऊर्जा, धन और समय का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। इस दौरान कार्य विशेष के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर भी अचानक निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद और नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध का समय ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में आपको अपने कारोबार से जुड़े बड़े फैसले इसी दौरान करने चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप कुछ चीजों को लेकर खुद को असमंजस की स्थिति में पा सकते हैं। ऐसे में इस दौरान कोई बड़ा फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। नौकरीपेशा जातकों इस सप्ताह अपने कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं बेहतर तरीके से पूरे करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा पूर्व में की गई न सिर्फ आपकी मेहनत बेकार जा सकती है, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की डांट भी सुननी पड़ सकती है।

कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में मनचाही सफलता और खुशियां मिले तो आपको अपने कार्य और व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना होगा और अपने शुभचिंतकों को नाराज करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपकी किसी बात या व्यवहार से आपके अपने नाराज हो सकते हैं। वाद–विवाद बढ़ने पर वर्षों से बने रिश्ते में दरार आ सकती है। करियर–कारोबार से लेकर घर–परिवार में सब कुछ अच्छा बना रहे इसके लिए दूसरों से अपेक्षा करने करने की बजाय आपको खुद ही आगे बढ़कर प्रयास करना होगा।

यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में कनिष्ठ लोगों के साथ रुखा व्यवहार न करें और अपने वरिष्ठ लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। यदि आप व्यवसायी हैं तो शार्टकट तरीके से लाभ कमाने से बचें और कागजी काम पूरे करके रखें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन का लेनदेन सावधानी के साथ करें।

तुला

तुला राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम और रिश्ते–नाते की दृष्टि से मध्यम फलदायी रहने वाला है।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर–कारोबार से जुड़ा कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह तुला राशि का नौकरीपेशा जातक हो या फिर व्यवसाय से जुड़ा कारोबारी, वह अपना शत प्रतिशत अपने कार्य में देता हुआ नजर आएगा।

खास बात कि उसके प्रयासों को सौभाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और सीनियर आपके कामकाज की खुले मन से प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के अंत तक आपको बड़ा पद अथवा अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी नये कारोबार की शुरुआत करने अथवा किसी बड़ी डील को फाइनल करने के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। यदि आप लंबे समय से रोजी–रोजगार के लिए प्रयासरत थे तो सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है।

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए है। इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभता–सफलता की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। करियर–कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। कार्यक्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। यदि आपके कारोबार में बीते समय से कोई अड़चन आ रही थी इस सप्ताह वह किसी व्यक्ति विशेष की मदद से दूर हो जाएगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आप उसके विस्तार की योजना पर काम करेंगे। आपकी योजना को साकार रूप देने के लिए आपके शुभचिंतक और परिजन पूरी मदद करेंगे। इस संबंध में घर–परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह लाभदायी साबित होगी। यह सप्ताह पठन–पाठन एवं शोध से जुड़े कार्यों को करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा।

धनु

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन के नये अवसरों को लेकर आने वाला है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको आलस्य और आशंका को त्याग कर कठिन परिश्रम और प्रयास करना होगा। इस सप्ताह यदि आप अपने धन, समय और उर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आपको आशा से अधिक सफलता और लाभ मिल सकता हैं। वहीं इसकी अनदेखी करने पर बनते काम बिगड़ जाने से मन में निराशा के भाव जाग सकते हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह खुले हाथ धन खर्च करने से बचना चाहिए अन्यथा सप्ताह के अंत तक उन्हें उधार मांगने की नौबत आ सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको कारोबार में लाभ तो होगा लेकिन साथ ही साथ खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है। परीक्षा–प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के मध्य में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है।

मकर

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार–चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने करियर–कारोबार में आ रही अड़चनों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र और कारोबार के अलावा निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं भी आपकी बड़ी चिंता का कारण बनेंगी। हालांकि जीवन के कठिन समय में आपके शुभचिंतक एवं परिजन काफी मददगार साबित होंगे और काफी हद तक आप इन समस्याओं का समाधान खोजने में भी कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य में किसी भी कार्य को करते समय विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस दौरान स्वजनों के साथ बात–व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आएं अन्यथा लंबे समय से बने हुए रिश्तों में दरार आ सकती है। इस सप्ताह खर्च की अधि.कता के चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर–कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है।

कुंभ

जीवन में आने वाली छोटी–मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। करियर और कारोबार की दिशा में किए गये प्रयास सफल होंगे और आपके पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी।

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिर सकता है। सत्तापक्ष से जुड़े लोगों के साथ आपका मेल–मिलाप बढ़ेगा। आपके मान–सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपनी सूझबूझ से अपने विरोधियों पर काबू पाने में कामयाब होंगे। कुंभ राशि के जो जातक तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रानिक का कारोबार करने वालों को बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति से कार्य विशेष के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

मीन

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय जहां अनुकूल तो वहीं उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों सप्ताह की शुरुआत में ही निबटाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इसी दौरान पूरे मनोयोग से रोजी–रोजगार के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से भूमि–भवन से जुड़े विवाद का समाधान निकल सकता है। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि उनकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ भी सकती है।

ऐसे में अपना काम निकलवाने के लिए लोगों की प्रशंसा करने में जरा भी कंजूसी न करें और सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके घर में कोई धार्मिक अथवा मांग.लिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा–पाठ में बीतेगा।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

गाज़ीपुर डेयरी फार्म में अवैध झुग्गियों और कथित अवैध गतिविधियों का खुलासा : समाज सेवक मनोज भाटी को जान से मारने की धमकी मिली

'पुलिस के कार्रवाई न करने पर उठे सवाल : मनोज भाटी ने डीसीपी ईस्ट दिल्ली के पास लिखित शिकायत की'

रवींद्र आय

ईस्ट दिल्ली के गाज़ीपुर डेयरी फार्म इलाके में क्ैप्ठ सरकारी ज़मीन पर बनी अवैध झुग्गियों, कथित अवैध गतिविधियों और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई न करने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद, ग्राउंड लेवल पर तनाव, धमकियां और कानून–व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दे सामने आ रहे हैं।

स्थानीय सोशल वर्कर मनोज भाटी ने ष्इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ष् को दिए एक इंटरव्यू में आरोप लगाया कि गाज़ीपुर डेयरी फार्म के ठ ब्लॉक, लेन नंबर 7 में क्ैप्ठ की ज़मीन पर बनी झुग्गियों में लंबे समय से अवैध कब्ज़ा और कथित अवैध गतिविधियां चल रही हैं। उनका कहना है कि मीडिया में इस मुद्दे को पब्लिसाइज़ करने और उठाने के बाद, उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं।

'गैरकानूनी कब्ज़े और हाई कोर्ट के आदेश के बाद तनाव बढ़ा'

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विवादित ज़मीन दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (क्ैप्ठ) की है, जिस पर सालों से गैरकानूनी कब्ज़े का आरोप है। पिटीशनर धर्मेंद्र दास की अर्ज़ी के बाद, हाई कोर्ट ने कब्ज़ा हटाने के लिए एक डेडलाइन तय की थी।

हालांकि, कार्रवाई शुरू होने पहले ही लोकल लेवल पर विरोध और तनाव पैदा हो गया है। लोकल सूत्रों के मुताबिक, कब्ज़ा हटाने की कार्रवाई के बारे में सुनकर, कई बाहर से आए बंगाली परिवारों में असुरक्षा की भावना महसूस हुई और उन्होंने सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया।

'सोशल मीडिया पर धमकियांरू डर का माहौल'

मनोज भाटी के मुताबिक, उन्हें बंगाली मुजाहिदा नाम की एक महिला के कथित तौर पर चलाए जा रहे नेटवर्क से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स, खासकर /उवदपींद–र3 और /नीइपतेपदही–ी8प, से धमकी भरे मैसेज मिले, जो गैरकानूनी कब्ज़े से जुड़े थे। मैसेज में साफ लिखा था कि उन्हें देखते ही गोली मारने और बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी।

उनका आरोप है कि इलाके में डर और दबाव का माहौल बनाने के लिए पब्लिक कमेंट्स के तौर पर धमकियां पोस्ट की गईं। भाटी का कहना है कि ये सिर्फ पर्सनल धमकियां नहीं हैं, बल्कि गैर–कानूनी कामों के खिलाफ बोलने वालों को चुप कराने की कोशिश है। मनोज भाटी पहले भी वहां रहने वाला. ` की गैर–कानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश कर चुके हैं, जिसमें गैर–कानूनी मस्जिदें, मदरसे और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की फेक आई–डी शामिल हैं।

'पुलिस के कार्रवाई न करने का आरोप'

मनोज भाटी ने कहा कि उन्होंने गाजीपुर मंडी पुलिस स्टेशन के ै भ्व् बाल कृष्ण उपाध्याय को मौखिक रूप से और व्हाट्सप्प के ज़रिए डिजिटल सबूत, स्क्रीनशॉट और डिटेल्स भेजे, और कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है किरू

- ☐ अभी तक थ्प्त् दर्ज नहीं की गई है।
- ☐ उन्हें साइबर जांच शुरू होने की जानकारी भी नहीं दी गई है।
- ☐ पीड़ित की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

ये आरोप गाज़ीपुर की लोकल पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हैं।

'क्ब्च् ईस्ट दिल्ली को लिखित शिकायत'

19 फरवरी, 2026 को, मनोज भाटी ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, ईस्ट दिल्ली को तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए एक लिखित शिकायत दी। शिकायत में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अब भी इंसाफ नहीं मिला, तो वे कानून पर विश्वास नहीं रखेंगे।

उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांगें की हैंरू

- ☐ धमकी के मामले में तुरंत थ्प्त् दर्ज की जाए।
- ☐ संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट्स की साइबर जांच की जाए।
- ☐ आरोपियों की पहचान की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए।
- ☐ उन्हें और उनके परिवारों को पुलिस सुरक्षा दी जाए।
- ☐ लोकल पुलिस स्टेशन की लापरवाही की जांच की जाए।

'गैर–कानूनी गतिविधियों के आरोप और इलाके की चिंताएं'

स्थानीय लोगों का दावा है कि विवादित झुग्गियों में कथित तौर पर गैर–कानूनी गतिविधियां चल रही हैं, जिससे इलाके में क्राइम और असुरक्षा बढ़ गई है। हालांकि, इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच और ट्रांसपेरेंट कार्रवाई नहीं की गई, तो यह मामला कानून–व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।

'कानून और न्याय व्यवस्था पर बड़े सवाल'

कानूनी जानकारों का मानना घ्है कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर धमकी देना कानून के राज को चुनौती देना है। सोशल मीडिया के ज़रिए क्रिमिनल धमकी देना इंडियन पीनल कोड और प्ज् एक्ट के तहत एक गंभीर अपराध माना जाता है।

यह मुद्दा अब सिर्फ़ ज़मीन का झगड़ा नहीं रहा। यह एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, नागरिकों की सुरक्षा, कोर्ट के आदेशों का पालन और कानून के राज की विश्वसनीयता से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन गया है।

ये मुद्दे एडमिनिस्ट्रेशन पर नागरिकों के भरोसे पर भी असर डालेंगे।

(ग्राउंड रिपोर्ट : रवींद्र आर्य
समाज सेवक मनोज भाटी
+91 98998 80288

पुलिस स्टेशन	
बाग-ए-बहू	2459777
बख्शी नगर	2580102
बस स्टैंड	2575151
शहर	2543688
गांधी नगर	2430528
गंग्याल	2482019
नौबाद	2571332
पक्का डांगा	2548610
रेलवे स्टेशन	2472870
सैनिक कॉलोनी	2462212
सतवारी	2430364
चन्नी हिम्मत	2465164
ट्रांसपोर्ट नगर	2475444
त्रिकुटा नगर	2475133
गांधी नगर	2459660
एसएसपी शहर	2561578
एसपी शहर उत्तर	2547038
एसपी दक्षिण	2433778
सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ	
इंडियन एयर लाइन्स	
शहर कार्यालय	2542735
एयर पोर्ट	2430449
जेट एयर वेज़	2453999
सिटी ऑफिस	2573399
रेलवे	
रेलवे पूछताछ	131, 132, 2476407
बुकिंग	2470318
आरक्षण	2470315
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्टेशन	

बख्शी नगर	2543557
गांधी नगर	2430786
कंपनी बाग	2542582
नया प्लॉट	2573429
पंजतीर्थी	2547537
दूरसंचार विभाग	
डायरेक्ट्री पूछताछ	197
फॉल्ट रिपेयर	198
ट्रंक बुकिंग	180
बिलिंग शिकायत	2543896
जम्मू नगर पालिका	
जं. लाइन्स	2578503
प्रशासन अधिकारी	2542192
स्वास्थ्य अधिकारी	2547440
डाक सेवाएँ	
मुख्य डाकघर शहर	2543606
गाँधी नगर	2435863
अग्निशमन सेवाएँ	
नियंत्रण कक्ष	101,132, 2476407
शहर	2544263
गाँधी नगर	2457705
नहर	2554064
गंग्याल	2480026
रसोई गैस डीलर	
चिनाब गैस	2547633
गुलमौर गैस	2430835
जैकफेड	2548297
एचपी गैस	2578456
शिवांगी गैस	2577020
तवी गैस	2548455
पावर हाउस	
गाँधी नगर	2430180
नहर रोड	2554147
जानीपुर	2533828
नानक नगर	2430776
परेड	2542289

सतवारी कैंट	2452813
अस्पताल	
जीएमसी अस्पताल	2584290
एस.एम.जी.एस. अस्पताल	2547635
सी.डी. अस्पताल	2577064
डेंटल अस्पताल	2544670
गांधी नगर अस्पताल	2430041
सरवाल अस्पताल	2579402
जी.बी. पंत कैंट अस्पताल	2433500
आयुर्वेदिक कॉलेज	2543661
सी.आर.पी. अस्पताल	2591105
आचार्य श्री चंदर	2662536
मानसिक अस्पताल	2577444
स्वामी विवेकानंद	2547418
ब्लड बैंक	2547637
एम्बुलेंस	2584225, 2575364
एम्बुलेंस (रेड क्रॉस)	2543739
नर्सिंग होम	
मदन अस्पताल	2456727
मेडिकेयर	2435070
त्रिवेणी नर्सिंग होम	2452664
सुविधा नर्सिंग होम	2555965
अल. फिरदौस नर्सिंग होम	2545050
आस्था नर्सिंग होम	2576707
बी एन चैरिटेबल ट्रस्ट	2505310
चोपड़ा नर्सिंग होम	2573580
हरबंस सिंह मेम हॉस्पिटल	2541952
जीवन ज्योति	2576985
यूद्धवीर नर्सिंग होम	2547821
मीडियाएड नर्सिंग होम	2466744
सीता नर्सिंग होम	2435007
विभूति नर्सिंग होम	2547969
रामेश्वर नर्सिंग होम	2580601
बी एन चेरिटेबल	2555631
महर्षि दयानंद	2545225

नगरी परोल में मिशन युवा के तहत उद्यमिता जागरूकता मेला आयोजित

सबका जम्मू कश्मीर

नगरी/कठुआ : युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नगरी परोल में मिशन युवा के तहत एक दिवसीय उद्यमिता–सह–जागरूकता मेले का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला रोजगार एवं परामर्श केंद्र ने जिला प्रशासन कठुआ के सहयोग से आयोजित किया।

मेले में युवाओं को सरकारी योजनाओं के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू करने की जानकारी दी गई। सहायक निदेशक रोजगार पियूषा खजूरिया ने मिशन युवा की विशेषताओं, पात्रता और मिलने वाली सहायता के बारे में सरल भाषा में विस्तार से बताया।

कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त कठुआ सुरेंद्र मोहन शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन युवा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार पंजीकरण कर आर्थिक सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम में सफल उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा कर युवाओं को प्रेरित किया।

मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया।

नगरी – ऐरवा रोड पर ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अनदेखी, स्कूली छात्रों की जान से खिलवाड़

सबका जम्मू कश्मीर

नगरी/कठुआ : नगरी से ऐरवा, सुमवान व बरोनटी तक चलने वाले मिनी ऑटो चालक ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर ऑटो की छतों पर सवारियां, विशेषकर स्कूली छात्र–छात्राओं को बैठाकर सफर कराया जा रहा है, जो किसी भी बड़े हादसे को दावत देने जैसा है। रोजाना स्कूल की छुट्टी के बाद बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं और आम यात्री घर लौटने के लिए इन मिनी ऑटो का सहारा लेते हैं, लेकिन क्षमता से अधिक सवारियां और छतों पर बैठाकर ले जाना यात्रियों की जान को गंभीर खतरे में डाल रहा है। थोड़ी सी चूक किसी भी समय जानलेवा दुर्घटना में तब्दील हो सकती है।

हालांकि ट्रैफिक विभाग, कठुआ द्वारा आसपास के क्षेत्रों में नियमित रूप से नाके लगाकर नियम तोड़ने वालों के चालान काटे जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन ऑटो चालकों पर भी सख्त कार्रवाई होगी जो रोजाना नियमों की अनदेखी कर लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं।

क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि किसी अनहोनी से पहले हालात पर काबू पाया जा सके।

मह गांव में माता रानी के जागरण में पहुंचे डीडीसी नगरी संदीप मजोत्रा

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : संदीप मजोत्रा ने मह गांव में आयोजित माता रानी के जागरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने माता रानी के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त किया।

कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने जागरण समिति और गांववासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करते हैं।

डीडीसी संदीप माजोत्रा ने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाजहित के कार्यों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि क्षेत्र के विकास और सामाजिक कार्यों में वह अपना पूरा सहयोग देते रहेंगे।

जागरण में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और धार्मिक भजनों के साथ वातावरण भक्तिमय बना रहा।

जम्मू और उधमपुर में 7 ड्रग तस्कर गिरफ्तार; 2 पिस्तौल और हेरोइन जब्त

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : पुलिस ने शनिवार को बताया कि जम्मू और कश्मीर के जम्मू और उधमपुर जिलों में अलग–अलग स्थानों से सात कथित नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरएस पुरा निवासी बलविंदर कुमार और सनी कुमार को जम्मू शहर के गांधी नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया और उनके पास से एक पिस्तौल, एक मैगज़ीन और 21 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। उन्होंने बताया कि सांबा निवासी मोहम्मद इकबाल और अमित कुमार उर्फ छज्जोगी को भी गांधी नगर से गिरफ्तार किया गया और उनके पास से एक पिस्तौल और 146 ग्राम हेरोइन जब्त की गई।

इंडियन आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नौशहरा ने सरिया मिडिल स्कूल में वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे मनाया

सबका जम्मू कश्मीर

नौशहरा : वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के मौके पर, ऐस ऑफ स्पेड्स डिवीज़न की झंगर बटालियन ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नौशहरा के साथ मिलकर सरिया मिडिल स्कूल में एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया। इसका मकसद युवा स्टूडेंट्स में बराबरी, सबको साथ लेकर चलने और सामाजिक मेलजोल के मूल्यों को बढ़ावा देना था। इस इवेंट का मकसद स्टूडेंट्स को एक मज़बूत और आगे बढ़ने वाले समाज के निर्माण में न्याय, बराबर मौके और अलग–अलग तरह के लोगों के सम्मान के महत्व के बारे में बताना था। इंडियन आर्मी के अधिकारियों और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधियों ने लोगों को संबोधित किया और सामाजिक ज़िम्मेदारी के महत्व और एक निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाले देश को बनाने में युवाओं की भूमिका पर ज़ोर दिया।

इंटरैक्टिव सेशन, चर्चा और मोटिवेशनल बातों ने स्टूडेंट्स को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इज्ज़त, एकता और आपसी सम्मान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए बढ़ावा दिया। प्रोग्राम में स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स ने जोश के साथ हिस्सा लिया, जो जागरूकता और पॉजिटिव सामाजिक बदलाव लाने के लिए एक जैसा कमिटमेंट दिखाता है। इस मिली–जुली पहल ने इंडियन आर्मी के न सिर्फ देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, बल्कि कम्युनिटी डेवलपमेंट और देश बनाने की कोशिशों में भी योगदान देने के लिए लगातार डेडिकेशन को पक्का किया। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नौशेरा ने ज़िम्मेदार नागरिकों को तैयार करने और ज़मीनी स्तर पर न्याय और बराबरी की नींव को मज़बूत करने के लिए मिलकर कोशिश करने की अहमियत पर ज़ोर दिया। यह इवेंट स्टूडेंट्स के अपने समुदायों में निष्पक्षता, दया और सबको साथ लेकर चलने की वैल्यूज़ को बनाए रखने के एक साथ वादे के साथ खत्म हुआ।

डुग्गर दा रत्न अवॉर्ड से सम्मानित होंगे मॉडल अभिनेता दिव्यांश बाबा

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : संवेदना समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मॉडल एवं अभिनेता दिव्यांश बाबा को इस वर्ष के प्रतिष्ठित "डुग्गर दा रत्न अवॉर्ड" से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें पंजाबी और डोगरी भाषा के प्रचार–प्रसार में उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन रीजनल रिसर्च लबोरटरी जम्मू में किया जाएगा, जहां उन्हें "लेजेंड्स आइकॉनिक अवॉर्ड" भी प्रदान किया जाएगा। दिव्यांश बाबा ने इस सम्मान के लिए संवेदना समिति और उसके अध्यक्ष केशव चोपड़ा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अभिनय उनके लिए अपनी संस्कृति की सेवा का माध्यम है और वे डोगरी भाषा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है, जो उन्हें आगे भी जम्मू की सांस्कृतिक विरासत के लिए समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

ऑपरेशन सद्भावना के तहत सीमा क्षेत्र में भारतीय सेना की पहल

सबका जम्मू कश्मीर

कड्याला/गुजर चक (मढ़ीन) : भारत–पाक सीमा से सटे जीरो लाइन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा 'ऑपरेशन सद्भावना' के तहत गुरुवार और शुक्रवार को दो दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गवर्नमेंट हाई स्कूल कड्याला और गुजर चक में आयोजित किए गए।

गवर्नमेंट हाई स्कूल कड्याला में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना तथा सेना और स्थानीय समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करना था। इस दौरान 96 विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री वितरित की गई, जबकि 10 मेधावी विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।

वहीं गुजर चक में भारतीय सेना द्वारा एक मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया।

कार्यक्रम का नेतृत्व 23 पंजाब बटालियन के कर्नल पंकज राठी ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें अनुशासन, मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मेजर अर्नव वर्मा भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में सरपंच मोहन लाल, नायब सरपंच कुलदीप कुमार, हायर सेकेंडरी स्कूल चकड़ा के प्राचार्य मदन लाल और स्कूल की मुख्याध्यापिका रमा कुमारी सहित कई स्थानीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

सेना अधिकारियों ने विद्यार्थियों को शिक्षा, अनुशासन और देशभक्ति का महत्व समझाते हुए कहा कि देश के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका होती है।

स्कूल प्रशासन और स्थानीय लोगों ने इस पहल के लिए भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में सेना और विद्यार्थियों के बीच सकारात्मक संवाद हुआ, जिससे बच्चों में उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिला।

तरसेम पाल सैनी बने जिला किसान कांग्रेस कठुआ के अध्यक्ष

सबका जम्मू कश्मीर

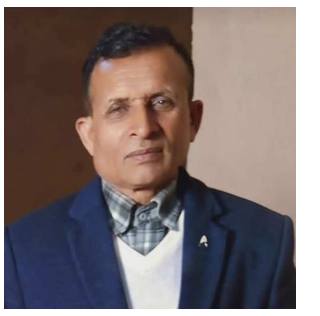

कठुआ : ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने गुरुवार को

जम्मू–कश्मीर प्रदेश किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दे दी

इसी क्रम में जिला कठुआ में लंबे समय से कांग्रेस कमेटी में सेवाएं दे रहे तरसेम पाल सैनी को जिला किसान कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

उनकी नियुक्ति पर सहयोगियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि तरसेम पाल सैनी संगठन के प्रति पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे, जैसा वे पहले भी करते आए हैं।

नवनियुक्त जिला अध्यक्ष तरसेम पाल सैनी ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन को मजबूत करने और किसानों की समस्याओं को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाने का कार्य जारी रखेंगे।

उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आवाज बुलंद करना उनकी प्राथमिकता रहेगी।

नट मंच ने डोगरी साहित्यकार यशपॉल निर्मल को किया सम्मानित

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : नट मंच ने अपने संस्थापक सदस्य और प्रसिद्ध डोगरी साहित्यकार यशपॉल निर्मल को जम्मू–कश्मीर सरकार पुरस्कार 2026 मिलने पर सम्मानित किया। इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें साहित्यकारों और मंच के सदस्यों ने भाग लिया।

यशपॉल निर्मल ने डोगरी सहित अन्य भाषाओं में 90 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने डोगरी भाषा और साहित्य के संरक्षण व प्रचार–प्रसार में अहम योगदान दिया है। खासतौर पर बाल साहित्य और अनुवाद के क्षेत्र में उनके कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

पहले भी मिल चुके हैं कई सम्मान

निर्मल को पिछले वर्षों में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें कृ

मियां डिडो के लिए नेशनल ट्रांसलेशन प्राइज (2014)

छुट्टियां के लिए प्यारी देवी घासी राम सिहाग चिल्ड्रन्स लिटरेचर अवार्ड (2018)

1008 डोगरी हाइकु के लिए सिया राम सहगल अवार्ड (2020)

अनुवाद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए डॉ. गार्गी गुप्ता द्विवागीश अवार्ड (2023द्24)

मंच पदाधिकारियों ने की सराहना

कार्यक्रम में नट मंच के अध्यक्ष तरुण शर्मा ने निर्मल के आजीवन समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत का सच्चा प्रतिनिधि बताया। उन्होंने कहा कि निर्मल का कार्य युवा लेखकों को प्रेरित करता है और जम्मू–कश्मीर के साहित्यिक माहौल को मजबूत बनाता है।

इस अवसर पर नट मंच के उपाध्यक्ष गुरमीत दत्ता सहित कई साहित्यकार मौजूद रहे। सभी ने निर्मल को बधाई देते हुए उनकी उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया।

कार्यक्रम का समापन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। नट मंच ने डोगरी भाषा, साहित्य और क्षेत्र की सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे भी समर्थन और बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया।

पूँछ में लापता महिला सकुशल बरामद, मिलाया गया परिवार से

राजेश कुमार

पुंछ : गुरसाई नल्लाह क्षेत्र की रहने वाली 27 वर्षीय फिरोज़िया बीबी, पत्नी जमील अहमद, के लापता होने की रिपोर्ट 31 जनवरी 2026 को गुरसाई थाने में दर्ज की गई थी।

रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने महिला की तलाश के लिए अभियान शुरू किया।

संभावित स्थानों पर जांच की गई और लगातार निगरानी रखी गई।

पुलिस की मेहनत रंग लाई और महिला को सकुशल बरामद कर लिया गया। बरामदगी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर महिला को सुरक्षित रूप से उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इसके साथ ही गुमशुदगी की रिपोर्ट बंद कर दी गई।

डिस्ट्रिक्ट पुलिस पूँछ ने कहा कि वह नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और गुमशुदगी जैसे मामलों में त्वरित कार्रवाई जारी रखेगी।

नगरी रोड स्थित शिव मंदिर में माता की मूर्ति की विधिपूर्वक स्थापना

सबका जम्मू कश्मीर

मढ़ीन/नगरी : नगरी रोड के साथ लगते शिव मंदिर में माता की मूर्ति की विधिपूर्वक स्थापना की गई। इस धार्मिक आयोजन को लेकर क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला।

दो दिवसीय हवन–यज्ञ के बाद हुआ स्थापना कार्यक्रम

मूर्ति स्थापना से पहले मंदिर परिसर में दो दिन तक हवन–यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूजा–अर्चना कर क्षेत्र की सुख–शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पैरामेडिकल साइंस के डायरेक्टर डॉ. मधुसूदन विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने भी हवन–यज्ञ में भाग लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया।

स्थानीय लोगों की रही सक्रिय भागीदारी

मंदिर परिसर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में स्थानीय लोगा. ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा में भाग लिया।

लंगर का किया गया आयोजन

मूर्ति स्थापना के बाद मंदिर परिसर में लंगर का आयोजन भी किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया और आयोजन को सफल बनाया।

NOTICE

I Shishu Paul Singh S/o Sat Paul Singh R/o Nagri Parole, Distt Kathua, Jammu have applied for the correction of my, my father's & nominee's name which has been wrongly written as Shishu Paul S/o Suresh Kumar & nominee Suresh Kumari instead of Shishu Paul Singh S/o Sat Paul Singh & nominee Suresh Devi in my PNB MetLife against Policy No. 21000360. Objection if any may be conveyed to concerned authority within a week of publication of this notice.

Ph No.: 8288976766

जीएलडीएम डिग्री कॉलेज हीरानगर में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का समापन, जागरूकता रैली निकाली गई

सबका जम्मू कश्मीर

हीरानगर : जीएलडीएम डिग्री कॉलेज हीरानगर में सड़क सुरक्षा विषय पर चल रही गतिविधियों की श्रृंखला का समापन विशेषज्ञ व्याख्यान और जागरूकता रैली के साथ किया गया।

कार्यक्रम कॉलेज की प्राचार्य डॉ. प्रज्ञा खन्ना के संरक्षण में आयोजित किया गया। रोड सेफ्टी क्लब के संयोजक प्रो. राकेश शर्मा ने युवाओं को यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

विशेषज्ञ वक्ता डॉ. गुरु शर्मा ने विद्यार्थियों को हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, गति सीमा का पालन करने और ड्राइविंग के दौरान मोबा. इल फोन का इस्तेमाल न करने की सलाह दी। उन्होंने दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक उपचार और सीपीआर देने की विधि भी समझाई तथा जरूरत पड़ने पर 108 एंबुलेंस सेवा पर तुरंत संपर्क करने को कहा।

कार्यक्रम में करीब 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉ. रजनी बाला ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कॉलेज के कई प्राध्यापक भी उपस्थित रहे।

समापन के अवसर पर कॉलेज परिसर में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें विद्यार्थियों ने "सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा" और "सावधानी हटी, दुर्घटना घटी" जैसे नारे लगाए।

कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को यह संद. श दिया गया कि सड़क सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

कल्यारी में 71 लाख की सड़क परियोजना का शिलान्यास

सबका जम्मू कश्मीर

जसरोटा/कठुआ : राजीव जसरोटिया ने कल्यारी क्षेत्र में लिंक रोड और पुलिया निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह परियोजना रोड सेक्टर (यूटी) कैपेक्स के तहत 71 लाख रुपये की लागत से बनाई जाएगी।

विधायक ने कहा कि सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है। इस सड़क के बनने से कल्यारी और आसपास के गांवों के लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा।

पैरामेडिकल कर्मचारियों के समर्थन में उतरे रमेश कुंडल, वेतन कटौती का आदेश वापस लेने की मांग

सबका जम्मू कश्मीर

हीरानगर : जिला महासचिव कांग्रेस रमेश कुंडल ने जम्मू–कश्मीर के पैरामेडिकल कर्मचारियों के समर्थन में बयान जारी करते हुए सरकार से ढाई दिन का वेतन काटने के फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि पैरामेडिकल कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं और कठिन परिस्थितियों में भी जनता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में उनका वेतन काटना उचित नहीं है। रमेश कुंडल ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हुए उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वेतन कटौती का आदेश वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के समर्थन में आंदोलन करने पर मजबूर होगी। उन्होंने सरकार से अपील की कि कर्मचारी वर्ग के साथ न्याय किया जाए और ढाई दिन की वेतन कटौती का फैसला तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर कठुआ में 2 से 8 मार्च तक मनाया जाएगा महिला सप्ताह

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : जिला आयुक्त राजेश शर्मा ने अंत. रराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2 से 8 मार्च तक जिले में महिला सप्ताह मनाने की घोषणा की। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर विस्तृत कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया।

बैठक में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी, एडीसी और एसडीएम मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी विभाग मिलकर कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

निर्धारित कार्यक्रमों के तहत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, वॉकाथॉन और मैराथन, कानूनी व सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा सत्र, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और प्रेरक व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा।

विशेष रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ताकि बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके।

उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम केवल औपचारिक न रहे, बल्कि इससे महिलाओं को वास्तविक लाभ मिले। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बैठक के अंत में कार्यक्रमों का विस्तृत कैलेंडर तैयार करने और पूरे जिले में व्यापक प्रचार–प्रसार करने के निर्देश दिए गए।

Before the Learned Executive Magistrate 1st Class, Tehsildar Nagri Parole, District Kathua (J&K UT)

Notice is hereby given to the general public that an application has been filed by Sh. Yash Pal S/o Sh. Achhar Dass, R/o Ward No. 12, Taraf Pain, Tehsil Nagri Parole, District Kathua (J&K UT) before the Learned Executive Magistrate 1st Class, Nagri Parole.

The applicant has prayed for issuance of directions to the Executive Officer, Municipal Committee Nagri Parole, to enter the date of death of Late Smt. Sumitra Devi W/o Sh. Achhar Dass, D/o Sh. Khazan Chand, M/o Maya Devi, who expired on 08.12.2018 at her residence at Taraf Pain, Tehsil Nagri Parole, District Kathua, in the official Death Register maintained by the Municipal Committee, as the same has not been recorded so far.

Any person having any objection regarding the entry of the above mentioned date of death in the official records may file his/her objections in writing before the Court of the Learned Executive Magistrate 1st Class, Nagri Parole, within 15 days from the date of publication of this notice.

In case no objection is received within the stipulated period, the matter shall be proceeded with in accordance with law.

Date: _____
Place: Nagri Parole

Sd/-
Sh. Yash Pal
(Applicant)

"पत्रकारों की आवश्यकता"
साप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर
'सबका जम्मू कश्मीर' हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जम्मू कश्मीर के सभी जिला के लिए पत्रकारों की आवश्यकता है इच्छुक पत्रकार संपर्क करें
योग्यता:
पत्रकारिता में अनुभव
उत्कृष्ट लेखन और संपादन कौशल
सोशल मीडिया घराने में काम करने का अनुभव
अपना बायोडाटा ई.मेल करें
sabkajammukashmir@gmail.com
संपर्क नंबर :
6005134383

साप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर
नाम परिवर्तन, तहसीलदार नोटिस,
शोक संदेश, गुमशुदा सूचना,
बेदखली, हुडा नोटिस, वैवाहिक,
सार्वजनिक सूचना इत्यादि विज्ञापन
MOB:- +91 60051-34383, +91 87170 07205

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ओपन जिला क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ

सबका जम्मू कश्मीर

हीरानगर/कठुआ : जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ओपन जिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के प्रारंभिक नॉक–आउट मुकाबले संबंधित उप–मंडल स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक उप–मंडल से विजेता टीम सेमी–फाइनल और फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी।

सेमी–फाइनल और फाइनल मुकाबले निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में खेले जाएंगे।

इसी कड़ी में रविवार को हीरानगर के खेल मैदान में टूर्नामेंट के दौरान हीरानगर के एसडीएम फुलेल सिंह ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और मैच शुरू होने से पहले औपचारिक पास करवाकर खेल का शुभारंभ कराया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने का सशक्त माध्यम है। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ समाज का निर्माण करना है।

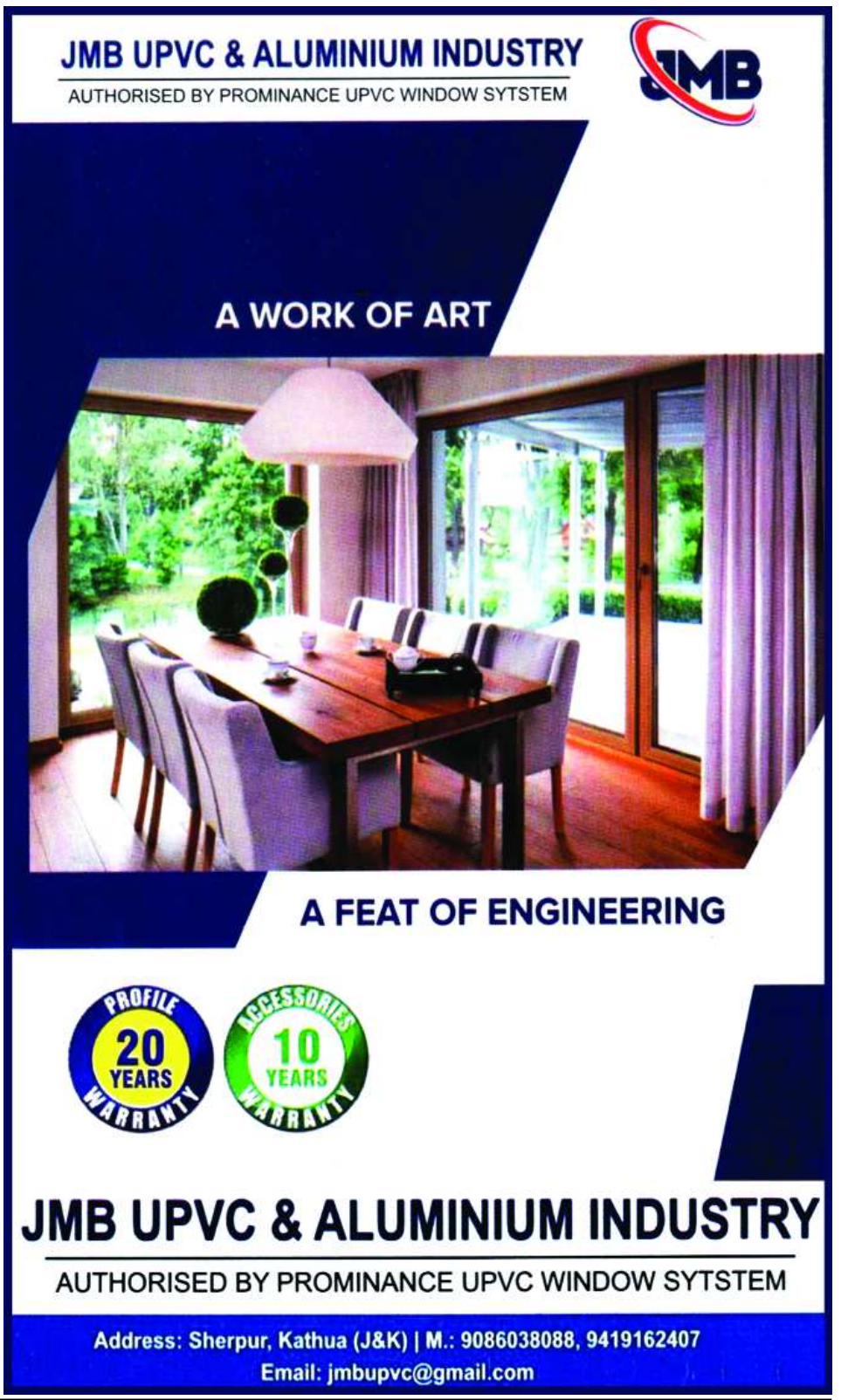

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशकः राज कुमार द्वारा एम/एस डी. आर प्रिंटिंग प्रेस, बैन बजाल्ता, तहसील जम्मू से मुद्रित एवं नगरी पैरोल नगरी, जिला कठुआ, जम्मू और कश्मीर पिन.कोड नंः 184151 । संपादकः राज कुमार